● वर्ष-3
● अंक-276
रायपुर, शुक्रवार
28 जून 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› अफ्रीका जा रहे हैं घूमने तो वहां पर ...

संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का संबोधन

मोदी ने राज्यसभा में कराया मंत्रियों का परिचय

नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद उनके अभिभाषण की प्रति बृहस्पतिवार को लोकसभा के पटल पर रखी गई और फिर सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कैबिनेट मंत्रियों, फिर राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और फिर राज्य मंत्रियों के नामों एवं उनसे संबंधित विभागों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने गत नौ जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को बृहस्पतिवार को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में इसकी घोषणा की। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को छह नए सदस्यों ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, झामुमो के डॉ सरफराज अहमद, भाजपा के प्रदीप कुमार वर्मा, बंसीलाल गुर्जर, माया नारोलिया और बालयोगी उमेशनाथ को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया।

द्रौपदी मुर्मू का संबोधन – राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले 10 साल के दौरान देश की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीबों का सशक्तीकरण रहा है तथा उनकी सरकार ने पहली बार गरीबों को अहसास कराया कि वह उनकी सेवा में है। मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में पहली बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों के जीवन की गरिमा से लेकर उनके स्वास्थ्य तक को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। मुर्मू ने कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हाल में हुए संसदीय चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में मतदान के कई रिकॉर्ड टूटने का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इन चुनाव के जरिए घाटी ने देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में 1975 में लागू आपातकाल को 'संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय' बताते हुए गुरुवार को कहा कि ऐसे अनेक हमलों के बावजूद देश ने असंवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त करके दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान, बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है और जब संविधान बन रहा था, तब भी दुनिया में ऐसी ताकतें थीं, जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थीं। लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिश रचने वाली विघटनकारी ताकतों से आगाह करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजने की जरूरत है। **(विस्तृत समाचार पेज 7 पर)**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री-निवास के दरवाजे गुरूवार को आम-नागरिकों के लिए पूरी तरह खुल गए। अब हर सप्ताह, गुरुवार के रोज, ये दरवाजे इसी तरह खुला करेंगे। इन खास दिनों में आम-औ-खास, कोई भी नागरिक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर सकेगा। **(विस्तृत समाचार पेज 3 एवं 7 पर)**

सांसदों ने नीट के मामले पर चर्चा के लिए दोनों सदन में नोटिस दिए

कांग्रेस के कई सांसदों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) से जुड़ी कथित अनियमितताओं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ''नाकामी'' के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद के दोनों सदन में नोटिस दिए हैं। पार्टी के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन और रंजीत रंजन ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। हुसैन ने अपने नोटिस में कहा कि सदन में आज के लिए सूचीबद्ध सभी कामकाज को स्थगित कर, नीट-यूजी और यूजीसी-नेट सहित विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने और एनटीए की ''नाकामी'' पर चर्चा कराई जाए। लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य मणिकम टैगोर ने इस विषय पर चर्चा की मांग करते हुए कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। कांग्रेस और 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के अन्य घटक दलों ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी से जुड़ी कथित अनियमितता का मुद्दा उठाने का फैसला किया है।

सदन में 'आपातकाल' पर बयानबाजियों को लेकर राहुल ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल ने सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं द्वारा संसद में आपातकाल पर की गई टिप्पणियों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित था और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल राव ने इस बारे में जानकारी दी। के सी वेणुगोपाल ने बताया कि 'यह एक शिष्टाचार भेंट थी। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुने जाने के बाद इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की।जब कांग्रेस महासचिव से सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी ने ओम बिरला के समक्ष सदन में उठाए गए आपातकाल के मुद्दे पर बातचीत की? इसके जवाब में वेणुगोपाल ने कहा कि 'हमने सदन के संचालन को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की और आपातकाल के मुद्दे पर भी बात हुई।' विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आपातकाल पर बयानबाजी को नजरअंदाज किया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि यह पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित था।

आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद बिरला ने वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाए जाने की निंदा की थी। इसके बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया था। बिरला ने कहा था कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था और मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाए थे। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल राव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है।

हम आशा करते हैं उपराज्यपाल कमीशन का उसके उद्देश्य के अनुरूप विशेषज्ञ के साथ पुनर्गठन करेंगे: वीरेन्द्र सचदेव

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन को अस्थाई रूप से भंग किये जाने का स्वागत किया है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की यह खेदपूर्ण है की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विकास कार्यों के माध्यम बनने योग्य दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन का राजनीतिक साथियों के आर्थिक उत्थान के लिए दुरुपयोग किया और एक अच्छे लिखित उद्देश्यों से बनाये गये कमीशन को उसके संस्थापन से ही विवादों में फंसा डाला। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा दिल्ली के विकास में एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन के स्थापना की घोषणा की थी और इसमे अपने अपने कार्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी थी पर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा डायलॉग कमीशन को आम आदमी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के स्थाई स्थाई करने का माध्यम डाला। कमीशन के पहले अध्यक्ष आशीष खेतान की तरह ही दूसरे अध्यक्ष जैस्मीन शाह भी विवादों मैं घिरे रहे। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण ना होगा की केजरीवाल ने विशेषज्ञों के नाम पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने का खेल किया और उसी के उदाहरण हैं आशीष खेतान एवं जैस्मीन शाह। इसी तरह आज बर्खास्त तीन सदस्यों को गत 3 वर्ष में बिना किसी विशेष योग्यता के करोड़ों रुपये वेतन के साथ भत्ते भी बांट दिए गये।

प्रमुख समाचार

क्यों वंदे भारत-गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड होने जा रही कम?

नई दिल्ली। देश में वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें अपनी तेज रफ्तार के लिए पहचानी जाती हैं। लेकिन अब रेलवे इन ट्रेनों की स्पीड कम करने के बारे में विचार कर रहा है। हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे ने कुछ ट्रेनों की स्पीड को कम करने की गुजारिश की है। दरअसल, पश्चिम बंगाल के कंजनजंगा में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद सुरक्षित ट्रेन परिचालन को लेकर रेलवे की चिंता बढ़ गई है। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 40 लोग घायल हुए थे। इसके बाद रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई रूटों पर कवच सिस्टम लगाने का काम तेजी से कर दिया है। रेलवे के द्वारा सभी रूट और ट्रेनों को स्वदेशी टक्कर रोधी उपकरण कवच से लैस करने के काम में तेजी लाई जा रही है। इसलिए सुरक्षा कवच मिलने तक तेज गति से चलने वाली ट्रेनों की गति कम की जा रही है। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के कुछ दिन बाद ही रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की जाने की बात

आपातकाल... अब ऐसा कभी नहीं होगा: धनखड़

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 1975 में आपातकाल लागू होने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अंधेरे में डूब गया था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। आपातकाल के काले दिनों को याद करते हुए धनखड़ ने कहा कि वे दिन फिर कभी नहीं आने दिये जायेंगे क्योंकि भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत हो चुका है, गांव, राज्य और केंद्र हर स्तर पर लोकतंत्र संवैधानिक रूप से सुदृढ़ हुआ है। दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की भूमिका की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्हें नए भारत का निर्माता बताया। सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले घाटे में चलने वाले उपक्रम सीईएल का विनिवेश करने की दिशा में कदम उठाये गये थे। लेकिन हाल ही में सीईएल ने बहुत उत्साहजनक प्रदर्शन करके लाभ अर्जित करने वाली मिनीरत्न कंपनी बन गयी।

भाजपा को दिल्ली बचाना है तो नीतीश को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा

नई दिल्ली। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा की मजबूरियों पर बात करते हुए कहा कि देश में लोकसभा का रिजल्ट ऐसा आया है कि भाजपा वाले चाहें भी तो नीतीश कुमार को नहीं हटा सकते हैं। आलम देखिए तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को हटाने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी को दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार बीजेपी से छूट जाएगी।

जन सुराज प्रशांत किशोर ने नीट पेपर लीक मामले पर अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि बीते 2 दिन पहले मुझे 1 लड़के ने बताया कि पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे दिन रात अपना हाड़ मांस गला कर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता किसी नेता को नहीं है। पढ़े-लिखे लड़के मुंबई में, दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और देखने वाली बात ये है कि 9वीं फेल नेता का लड़का तेजस्वी यादव बिहार में राज कर रहे हैं। बिहार के सभी लोगों को वो ज्ञान दे रहे हैं कि हमें गद्दी में बैठा दो तो हम सबको नौकरी दे देंगे।

बंगाल में हॉकरों को अतिक्रमण हटाने के लिए एक महीने का समय

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य भर में फुटपाथों से फेरीवालों को हटाने और सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर गुरुवार को एक आपात बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री बनर्जी ने फेरीवालों को फुटपाथ और सड़क के उन हिस्सों को खाली करने के लिए एक महीने का नोटिस जारी किया, जिन पर उन्होंने अतिक्रमण किया है। उन्होंने फेरीवालों के अतिक्रमण के इस मुद्दे पर एक सर्वेक्षण करने और 15 दिनों के भीतर अपने कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए एक समिति का गठन किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि मुझे किसी की आय का स्रोत छीनने या किसी को बेरोजगार करने का कोई अधिकार नहीं है। लाखों लोग फेरी लगाकर अपना परिवार चलाते हैं। एक महीने तक कोई बेदखली नहीं होगी। इस अवधि के दौरान, फेरीवालों को फुटपाथ खाली करना होगा। उन्होंने फुटपाथों और सड़कों के अतिक्रमण में कथित संलिप्तता को लेकर राजनीतिक नेताओं और पुलिस अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर कथित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है: योगी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी-112 द्वितीय चरण के तहत आधुनिक पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) को हरी झंडी दिखायी और साथ ही वातानुकूलित हेलमेट का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है और इसके लिए सुरक्षा व संरक्षा का बेहतर वातावरण होना चाहिए। सुरक्षा का वातावरण राज्य का दायित्व है और हमारी पुलिस इसका बखूबी निर्वहन करती है। सीएम योगी ने कहा, ''पिछले सात वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी नयी पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी नयी पहचान दिलाने में महती भूमिका का निर्वहन किया है। समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं देंगे तो पुलिस बल पिछड़ जाएगा। ऐसा होने से सबसे खतरनाक असर सामान्य नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ेगा। योगी ने यह भी कहा कि जनता का विश्वास एक बार व्यवस्था से हटा तो उसे बहाल करने में लंबे समय तक कवायद करनी पड़ेगी। समय के अनुरूप पुलिस का आधुनिकीकरण करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने बिना भेदभाव पारदर्शी प्रक्रिया से पुलिस बल में पुलिस भर्ती की और समुचित प्रशिक्षण भी कराया।

सत्ता के संख्या बल बनाम विपक्ष के मनोबल से तय होगी राजनीति

विनोद अग्निहोत्री

आम चुनावों के बाद भारत में 18वीं लोकसभा गठित हो गई। जवाहर लाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता हो गए, लेकिन लोकसभा में अब सामने अधीर रंजन चौधरी नहीं, बल्कि राहुल गांधी मुकम्मल नेता विपक्ष के रूप में हैं। भाजपा को भले ही अपने बलबूते पूरा बहुमत नहीं मिला, लेकिन सहयोगी दलों के साथ एनडीए गठबंधन को बहुमत से 21 सीटें ज्यादा मिलीं तो दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन भी 234 सांसदों के साथ इस बार ज्यादा हौसले के साथ सरकार को घेरने का खम ठोंक रहा है। वहीं इस बार सरकार कमजोर है और सहयोगी दलों के दबाव में काम करेगी जैसी तमाम आशंकाओं और अफवाहों को दरकिनार करते हुए सरकार ने भाजपा सांसद ओम बिरला को दूसरी बार भी स्पीकर चुनवा लिया। सहयोगी दल तो अड़े नहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार तो खड़ा किया, लेकिन के सुरेश के लिए मत विभाजन की मांग विपक्ष ने भी नहीं की। बेहद सौहार्द पूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नए नवेले नेता विपक्ष राहुल गांधी, ओम बिरला को अध्यक्ष आसन तक ले गए। इस घटना से उम्मीद जगी कि सत्ता पक्ष और प्रति पक्ष के बीच संवाद और सहयोग का एक नया रास्ता नई लोकसभा में खुल सकता है, लेकिन महज कुछ ही देर में यह उम्मीद तार तार हो गई जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 49 साल पहले 25 जून 1975 को देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पढ़ना शुरु किया।

इस प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए उसके संविधान बचाओ नारे का सरकार की ओर से करारा जवाब दिया गया और विरोध में कांग्रेस सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। दरअसल, जिस तरह विपक्ष खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में संविधान पर कथित खतरे को मुद्दा बनाया और उसका जवाब भाजपा कारगर तरीके से नहीं दे सकी, जिसका नुकसान उसे अपनी 63 सीटें गंवाकर चुकाना पड़ा। उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी भाजपा बेहद असहज है। विपक्ष सिर्फ चुनावों तक ही नहीं रुका, बल्कि नए सांसदों के शपथग्रहण के दौरान जिस तरह इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संविधान का गुटका संस्करण हाथ में लेकर %जय संविधान% का नारा लगाया, उससे सरकार और भी ज्यादा परेशान दिखाई दी।

यहां तक कि सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जब शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा लगाया तो स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि संविधान की शपथ तो आप ले ही रहे हैं। इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ कहा तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि चलो बैठो। भाजपा को डर है कि अगर विपक्ष संविधान को लेकर इसी तरह आक्रामक रहा तो इस साल और अगले साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा को नुकसान हो सकता है, इसलिए विपक्ष के संविधान मुद्दे की काट के लिए सत्ता पक्ष ने आपातकाल का निंदा प्रस्ताव लाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने और इंडिया गठबंधन के उन घटक दलों जो आपातकाल में सरकारी दमन के शिकार हुए थे, को इस मुद्दे पर कांग्रेस से दूर करने की कोशिश की है। सदन में जब लोकसभा अध्यक्ष आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव कर रहे थे तब जहां कांग्रेसी सांसद विरोध में नारे बाजी कर रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी राजद डीएमके जैसे दलों के सांसद चुप थे। संविधान को लेकर सरकार और स्पीकर के इन तेवरों ने विपक्ष को भी असहज कर दिया। अगले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र आने पर भी कांग्रेस ने ऐतराज जताया और कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी.वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ शिष्टाचार भेंट में उनसे कहा कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर तालमेल और संवाद बनाने के लिए आपातकाल जैसे मुद्दे पर प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिए था, क्योंकि इसे लेकर पहले ही कांग्रेस अपनी गलती मान चुकी है। दूसरी तरफ समाजवादी सांसद और दलित नेता आरके चौधरी ने सदन में स्थापित सेंगुल को राजशाही का प्रतीक चिन्ह बताते हुए इसे हटाने और इसकी जगह भारतीय संविधान स्थापित करने की मांग करके नई बहस छेड़ दी है। भाजपा जहां सेंगुल को भारतीय और तमिल संस्कृति का अमिट चिन्ह बताते हुए इसे राजदंड नहीं बल्कि धर्मदंड कहते हुए सदन में इसे स्थापित करने को सही ठहरा रही है वहीं विपक्ष संविधान को सर्वोपरि बताते हुए इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। इसके बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की बैठक में सदन में सरकार को नीट और तमाम मुद्दों पर घेरने की नई रणनीति बनाई गई।

ये घटनाएं बताती हैं कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद संवाद और सहयोगी की जो संभावना जताई जा रही थी, उसको पहले दिन ही नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि दस साल तक प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार और कमजोर विपक्ष के बीच संसद के भीतर जो असंतुलन था और सरकार ने जिस तरह विपक्ष की परवाह किए बिना तमाम कानून पारित करवाए, कई सांसदों को सदन से निर्लंबित किया गया और दस साल लोकसभा में विपक्ष नेता विहीन रहा और आखिरी पांच साल लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष भी नहीं रहा, लेकिन माना गया कि अब भाजपा के बहुमत से काफी दूर रह जाने और सहयोगी दलों के समर्थन से चलने वाली एनडीए सरकार का रुख अब विपक्ष के प्रति बदलेगा और पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत विपक्ष जिसके पास अब राहुल गांधी जैसा आक्रामक नेता विपक्ष है, उसके साथ सत्ता पक्ष के संवाद और सहयोग का दौर शुरु होगा क्योंकि विपक्ष की उपेक्षा अब संभव नहीं होगी।

पुलिस ने घेराबंदी कर छह नक्सलियों को किया गिरफ्तार

■ टेकलगुड़ा ब्लास्ट में थे शामिल

सुकमा। जगरगुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकलगुड़ा में बीते दिनों हुए ब्लास्ट में शामिल छह नक्सलियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली मौके पर आईईडी प्लान करने से लेकर घटना को अंजाम देने तक शामिल रहे हैं।

बीते दिनों टेकलगुड़ा में जावानों के लिए राशन लेकर जा रही फोर्स की कॉन्वे को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने एक बड़ा विस्फोट किया था, जिसमें ट्रक के पर कच्चे 30 फीट दूर तक जार गिरे थे और सड़क पर लगभग 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। वहीं, इस घटना में कोबरा के दो जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे बस्तर भर में हड़कंप मच गया था, क्योंकि पिछले छह महीने में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान नक्सलियों को हुआ था और इस दरमियान ब्लास्ट की घटना बस्तर भर में बड़ी थी जहां बौखलाए नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया।

मामले की पुष्टि करते हुए सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि जवानों की टुकड़ी सर्च अभियान पर निकली हुई थी और मुखबिरी से सूचना मिली थी कि नक्सलियों का जमावड़ा है। इसके बाद जवानों ने घेराबंदी कर सभी छह नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही एसपी ने बताया कि इस घटना में और भी लोग शामिल थे, जिनकी पहचान गिरफ्तार किए गए नक्सलियों से की जा चुकी है उनकी खोज भी जारी है।

नक्सलियों द्वारा लगाये गये प्रेशर आईईडी विस्फोट से भाई-बहन हुए घायल

दंतेवाड़ा। जिले के बारसूर थाना क्षेत्र अंर्तगत मंगनार में नक्सलियों द्वारा सुक्षाबलों को नुकसान पंहुचाने के लिए लगाये गये प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से भाई-बहन जुरूराम कतलामी एवं रूपा कतलामी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रेशर आईईडी विस्फोट की शिकार दोनों भाई-बहन बुधवार को अपने किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लौटते के दैरान हादसे का शिकार हो गए। दोनों घायलों का उपचार दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में जारी है। विस्फोट से युवक जुरूराम कतलामी के पैरों में गंभीर चोटें आई है, वहीं उसकी बहन भी घायल है। दोनो घायलों का बुधवर रात में परिजनों ने घर पर ही इलाज किया, आज गुरूवार सुबह जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो दोनों को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल दोनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दंतेवाड़ा एएसपी आरके. बर्मन ने इसकी पुष्टि की है।

5 लाख के ईनामी नक्सलियों सहित 17 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियन लोन वर्राटू (घर वापस आईये) तथा शासन की पुनर्वास नीति के तहत जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा भटके हुए नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोडने के लिए लगातार संपर्क एवं संवाद कर शासन की नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में नक्सली कैडर का आत्मसमर्पण देखने को मिल रहा है।

इसी कड़ी में 5 लाख के ईनामी नक्सलियों सहित 17 नक्सलियों ने पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, पुलिस उप महानिरीक्षक (परि.) सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज विकास कठेरिया, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय (भा.पु.से.), नीरज यादव कमाण्डेंट 111 वीं वाहिनी सीआरपीएफ, अनिल कुमार प्रसाद कमाण्डेंट 230 वीं वाहिनी सीआरपीएफ, राजीव कुमार कमाण्डेंट 195 वीं वाहिनी सीआरपीएफ, द्वितीय कमान अधिकारी आसूचना शाखा सीआरपीएफ सत्यनारायण तंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा रामकुमार बर्मन के समक्ष एसपी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण कर दिया है। एसपी दंतेवाड़ा द्वारा आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत् 25-25 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि नकद प्रदाय किया गया एवं शासन की पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदाय करवाया जायेगा।

नक्सलगढ़ में पहली बार बजी स्कूल की घंटी

■ लाल सलाम के नारों की जगह वर्णमाला सीखेंगे बच्चे

सुकमा। अक्सर नक्सलवाद और नक्सली घटनाओं के लिए ही चर्चे में रहने वाला सुकमा जिला शिक्षा के शिक्षा क्षेत्र में नए बदलाव कर रहा है। जहां लाल सलाम के नारे ही गूंजा करते थे वहां अब स्कूल की घंटी और बच्चों की एबीसीडी सुनने को मिल रही है। यह सुखद तस्वीर सुकमा जिले के दुलेड़ एलमागुंडा की है, जहां आजादी के 77 साल के बाद स्कूल खुला है।

हालांकि स्कूल झोपड़ी में है, क्योंकि इन इलाकों में व्यवस्थाओं को अब तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब यहां बच्चे गांव में ही रहकर शिक्षा की अलख जला पाएंगे। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी मिली कि स्कूल अब गांव में ही खुलेगा तो ग्रामीणों ने मिलकर बच्चों के लिए एक अस्थाई स्कूल का निर्माण झोपड़ी के रूप में किया। गौरतलब है कि इन इलाकों में शिक्षा से कटाव की मुख्य वजह गांव-गांव में स्कूल न हो पाना भी बताया जाता है।

2006 में जब सलवा जुडुम शुरू हुआ था तो सारे गांव से लोग राहत शिविर में ले जाए गए थे। इस दौरान एक दो स्थानों पर खाली स्कूल और अस्पताल को अस्थाई रूप से सुरक्षा कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जिस वजह से नक्सली संगठन ने जिले भर के संवेदनशील इलाकों के स्कूलों व अस्पतालों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, ताकि इन भवनों में सुरक्षाबल कैंप ना लगा पाए।

इसके बाद से शिक्षा के हालात इन इलाकों में बदतर हो गए। अंदरुनी गांव के बच्चों को आश्रमों और पोटाकेबिनों में शिक्षा से जोड़ा गया, लेकिन 50 फीसदी से ज्यादा ग्रामीण अंदरूनी इलाकों में ही रह गए। जिनके बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जिन घरों में दो बच्चे होते हैं। एक बच्चे को घर में ही घर की देखभाल खेती बड़ी और घर के कामकाज के लिए रखा जाता है। जिस वजह से वह बच्चा स्कूल गांव में न होने की वजह से शिक्षा से नहीं जुड़ पाता।

प्रत्येक घर में एक बच्चे की अगर यह स्थिति है तो समझ लीजिए कि ऐसे कितने बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पाए। फिलहाल अंदरूनी इलाकों में सरकार अपनी पहुंच पकड़ मजबूत कर रही है और गांव में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। 26 जून को जब प्रदेश भर में शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम चलाया गया तो इस गांव के लिए बेहद खुशी का पल था। जब स्कूल गांव तक पहुंचा और बच्चे गांव में ही रहकर शिक्षा से जुड़ पाए अब वह बच्चा जो घर में देखभाल के लिए रोका जाता है। वह भी शिक्षा से अछूता नहीं रहेगा ।

गुटबाजी व हार की हताशा में डूबी कांग्रेस ने निगम में दो नेता प्रतिपक्ष बनाया: अवस्थी

जगदलपुर। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एवं निगम राजस्व विभाग सभापति आलोक अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम में दो-दो नेता प्रतिपक्ष बना कर स्वयं यह बता दिया है कि कांग्रेस के अंदरखाने में कितनी खींचतान और लड़ाईयां चल रही है। प्रदेश कांग्रेस से भेजे गये दो अनुभवी पर्यवेक्षकों से भी तय नहीं हो पाया कि 23 कांग्रेसी पार्षदों का नेता कौन होगा। गुटबाजी व हार की हताशा में डूबी कांग्रेस ने निगम में दो नेता प्रतिपक्ष बनाया। नगर निगम में कांग्रेस के द्वारा बड़ा और छोटा नेता प्रतिपक्ष बनाने की राजनीतिक घटना पहली बार हुई है।

आलोक अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की करतूतों के कारण प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में उन्हें कान पकड़ कर सत्ता से बाहर कर दिया। लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने झूठी कांग्रेस को सच्चाई का आईना दिखाकर भाजपा को ही चुना। हार की हताशा कांग्रेस के सर चढ़कर बोल रही है और कांग्रेस के नेता खेमे बाजी में बंटकर एकदूजे को निपटाने का खेल खुलकर खेल रहे हैं। दो- दो नेताप्रतिपक्ष बनाना इसका प्रमाण है। उन्होने कहा कि सत्ता सुख से दूर होने के बाद अब कांग्रेस के नेताओं में संगठन में बड़ा पद पाने की होड़ मची है। प्रदेश कांग्रेस के हस्तक्षेप के बाद भी बतौर विपक्ष कांग्रेस का मौजूदा संगठन नेता प्रतिपक्ष के लिये एक नाम तक नहीं चुन पाया।

भाजपा ने गठन किया शहरी क्षेत्र परिसीमन समिति

विधनसभा-लोक सभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय एवं पंचायतों के चुनाव का दौरा शुरू हो जायेगा। इसकी तैयारी शासन प्रशासन स्तर पर शुरू हो गई है। जिसके तहत राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के पहले शहरी क्षेत्र का परिसीमन करने का निर्देश जारी कर दिया है। जिसके बाद भाजपा ने इसके लिए परिसीमन समिति का गठन भी कर दिया है। भाजपा द्वारा गठित परिसीमन समिति में महापौर सफीरा साहू, एमआईसी सदस्य योगेन्द्र पाण्डे, रामाश्रय सिंह, वेदप्रकाश पाण्डे, संजय पाण्डे, नरसिंह राव, सुरेश गुप्ता, यशवर्धन राव को जगह दी गई है। वहीं एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम के प्रभारी मनीष पारख और सहप्रभारी किशोर लाल महावर को बनाया गया है।

सौंदर्यकरण हेतु कलेक्टर ने किया विभिन्न समाज, संघ के प्रमुखों से चर्चा

जगदलपुर। नगर निगम द्वारा चौक-चौराहों के विकास हेतु आयोजित बैठक में विभिन्न समाज, व्यापारी संघों से चर्चा के दौरान कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि शहर आपका है, शहर के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण में समुदाय के विचार और सलाह अति महत्वपूर्ण है।

शहर के विकास में सभी नागरिकों की सहभागिता होना आवश्यक है। नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य चौक एनएमडीसी चौक, एयरपोर्ट चौक, शहीद पार्क, कोतवाली चौक, अग्रसेन चौक के विकास और सौंदर्यीकरण पर चर्चाकर विकास कार्य हेतु उनको दायित्व लेने के संबंध में भी वार्ता की गई। जिसमें कुछ व्यापारी संघ और समाज ने अलग-अलग चौक के सौंदर्यीकरण के सहमति दी है।

नगर निगम आयुक्त ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों के विकास और सौंदर्यीकरण की प्रेजेंटेशन के माध्यम से विकास कार्यों की डिज़ाइन और लागत की जानकारी दी, साथ ही शहर के चौक-चौराहों के भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में भी चर्चा किए। कलेक्टर श्री विजय ने समाजों को चौकों - चौराहों के मिले दायित्व के तहत साफ सफाई और समुचित रख-रखाव की व्यापक सहभागिता निभाने का आग्रह किया। साथ ही अन्य समाजों को दायित्व लेने की अपील की। इस अवसर पर विभिन्न समाज के प्रतिनिधि, बस्तर परिवहन संघ, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बिल्डर्स संघ, शिल्पी संघ सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

बलौदाबाजार जिले में शीघ्र स्थापित होगा साथी बाजार

बलौदाबाजार। भारत सरकार की केंद्रीय को-आपरेटिव नाफेड के माध्यम से जिले में साथी बाजार स्थापित किया जाएगा। साथी बाजार बनाने के लिए भाटापारा में स्थल चयन प्रस्तावित है।इसके संचालन के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं का किसान उत्पादक कंपनी के रूप में गठन होगा। इसका गठन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से होगा। साथी बाजार स्थापना के सम्बन्ध में बुधवार को कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक लेकर जरुरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सोनी ने स्थानीय मांग के अनुरूप एफपीओ का चयन, स्थल चयन तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से उपयुक्तता के सम्बन्ध में अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त करने कहा। उन्होंने कहा कि साथी बाजार में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बड़ा प्लेटफार्म मिलेगा। बताया गया कि चैंबर आफ कामर्स एवं कैट की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथी बाजार में माडर्न रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, एग्रीमाल, कृषि सहायता केंद्र, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, दराज बाजार, ब्यूटीपार्लर, टेली मेडिसिन सेंटर, डेयरी फेडरेशन, प्याज संग्रहण यूनिट, कोल्ड स्टोरेज मिनी थियेटर, स्थानीय उद्यम तथा अन्य उद्यम भी खोले जाएंगे।

विनोबा एप से संचालित होंगी शिक्षा की गतिविधियां

दंतेवाड़ा। जिले के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जिले में विनोबा ऐप के साथ शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के लिए आचार्य विनोबा भावे शिक्षक सहायक कार्यक्रम संचालित हो रहा है। जिसके अंतर्गत आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सभी शैक्षणिक गतिविधियों को विनोबा ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एसके. अंबस्ता ने जिले के समस्त ब्लॉकों में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई और हायर सेकंडरी विद्यालयों से एक-एक शिक्षक के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन कर इसमें ब्लॉक स्तर पर पोस्ट ऑफ द मंथ के विजेताओं को बीईओ द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य शैक्षणिक गतिविधियों को विनोबा एप के माध्यम से संचालित कर शिक्षकों के समय की बचत के साथ-साथ दैनिक कार्य आसान करने वाले मुख्य कार्यक्रमों को शिक्षकों के साथ साझा करना था। इसमें कक्षा 1 से 8वीं के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के साथ लर्निंग आउटकम बढ़ाने के लिए पढ़ेगा दंतेवाड़ा लिखेगा दंतेवाड़ा, जिले में 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम अच्छा करने के लिए मासिक टेस्ट, इसी के साथ-साथ एनएमएमएसई स्कॉलरशिप परीक्षा तथा नन्हे परिंदे सेंटर के बच्चों के लिए मासिक टेस्ट जो ओएमआर शीट के माध्यम से कराया जाएगा की जानकारी दी गई।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पुलिस ने दो अन्तर्राज्यीय मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार

मंदिर हसौद। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी का मामला सामने आया है। आरोपी अवैध तरीके से मवेशियों को वाहन में भरकर छत्तीसगढ़ से ओडिशा ले जा रहे थे। घटना को अंजाम देने वाले दो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेशनल हाइवे से ओडिशा की तरफ जा रहे वाहन में अवैध तरीके से मवेशी की तस्करी कर रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने स्टेडियम चौक के आगे हाईवे पर घेराबंदी की। मुखबिर के बताए वाहन वहां पहुंचा तो पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस दौरान वाहन की जांच की गई। जांच में पाया गया कि वाहन में मवेशी भरे हुए थे। आरोपी मवेशियों को वाहन में भरकर छत्तीसगढ़ से ओडिशा ले जा रहे थे। आरोपियों के पास इस संबंध में कागजात नहीं था। इस दौरान पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मवेशियों से भरे वाहन को जब्त कर लिया है। मामले में बुधवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी।

मकान में कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव

कोरबा। शारदा विहार स्थित अटल आवास के एक मकान में कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव जारी है। किरायेदार के रुप में रह रही महिला लगातार मकान मालिक के उपर हमलावर बनी हुई है। मकान में कब्जा पाने के लिए महिला टीपी नगर स्थित मकान मालिक के दुकान पहुंच गई और बीच चौराहे पर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं उसे मारने के लिए महिला हाथों में पेचकस लेकर काफी दूर तक दौड़ाया। मामले की शिकायत सीएसईबी पुलिस से की गई है। मकान में कब्जे को लेकर महिला का विवाद मकान मालिक से काफी पुराना है। महिला मकान खाली नहीं करना चाहती, जिसे लेकर महिला ने मानिकपुर चौकी में भी बवाल किया था। खुद के उपर पेट्रोल डालकर उसने आत्मदाह का प्रयास भी किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जेल से बाहर आकर महिला फिर उसी तरह की हरकतें कर रही है। पीड़ित लक्ष्मण जायसवाल ने बताया कि शारदा विहार अटल आवास में उसके मकान पर मनजीत कौर नामक महिला ने कब्जा किया है।

रात में चालक को आई झपकी डिवाइडर में जा घुसी बस

जगदलपुर। रायपुर से जगदलपुर 30 से अधिक यात्रियों को लेकर आ रही तेज रफ्तार बस आमागुड़ा के पास डिवाइडर में जा घुसी। इस घटना में बस चालक को गंभीर चोट आई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, बस में सवार यात्रियों की जान बाल-बाल बची है। बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी सुरेश जांगड़े ने बताया कि महिंद्रा ट्रेवलर्स की बस रायपुर से 30 से अधिक सवारियों को लेकर बुधवार की रात को निकली थी, गुरुवार की सुबह करीब तीन बजे के लगभग बस चालक को नींद की झपकी आने से तेज रफ्तार बस को रोक नही सका और डिवाइडर में जा घुसा। बस का हेल्पर पीछे सो रहा था। चालक के चेहरे में कांच का टुकड़ा घुस गया। बस के दुर्घटनाग्रस्त होते ही यात्रियों में खलबली मच गई। कुछ यात्रियों को हल्की-फुल्की चोट आई, घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली पार्टी मौके पर पहुंच घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल ले गए।

एसईसीएल सीएमओ के घर को चोरों ने बनाया निशाना

कोरबा। कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर ऑफिसर कॉलोनी में स्थित सी 5 में बुधवार रात बड़ी चोरी हुई। यहां रहने वाले एसईसीएल कुसमुंडा चिकित्सा विभाग के मुख्याधिकारी अरविंद कुमार के घर को चोरों ने निशाना बनाया। उन्होंने अपने घर हुई चोरी की सूचना कुसमुंडा थाना पुलिस को दी, जिस पर कुसमुंडा थाना प्रभारी रूपक शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं, डॉग स्क्वायड और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को भी सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गए। भीड़भाड़ वाले इलाके में चोरी की घटना से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। चोर पीछे दीवार कूदकर घर में घुसे, जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सोने चांदी के गहने और बड़ी मात्रा नकदी घर की अलमारी में रखी हुई थी। जिस वक्त ये घटना हुई घर पर कोई नहीं था। सूनेपन का फायदा उठाकर चोर बड़ी आसानी से घर में घुसकर हाथ साफ कर गए। मकान मालिक अरविंद ने बताया कि जब देर रात वापस आए और ताला खोलकर अंदर घुसे तब सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था।

सीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती

बीजापुर। रामपुरम सीएएफ कैंप में पदस्थ एक जवान ने गुरुवार सुबह खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जख्मी हुए जवान को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, जिले के भोपालपटनम ब्लॉक के रामपुरम सीएएफ कैंप में पदस्थ जवान मनोज दिनकर ने सुबह पांच बजे के करीब अपने सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर अपनी जान लेने की कोशिश की। सुबह कैंप के अंदर चली गोली की आवाज सुनकर वहां अफरातफरी मच गई। अन्य जवानों ने जब देखा कि जवान मनोज ने खुद को गोली मार ली तो अन्य जवानों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में घायल जवान का प्राथमिक उपचार किया गया। जवान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर कर दिया गया हैं। घटना की खबर लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि खबर लिखे जाने तक घटना का कारण सामने नहीं आ सका था।

नई व्यवस्था की वजह से रेलवे ने 14 से ज्यादा ट्रेनें की रद्द

बिलासपुर। भारतीय रेलवे ने फिर छत्तीसगढ़ से होकर आने-जाने वाली 14 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत सांकराईल-सांतरागाछी लिंक लाइन को आन्दुल स्टेशन से जोड़ने का कार्य ब्लॉक लेकर किया जाएगा। यह काम 29 जून से 8 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। इस वजह से 14 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल रहेंगी।

रद्द होने वाली गाडियां-

04 से 06 जुलाई 2024 तक एलटीटी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18029 एलटीटी- शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दिनांक 06 से 08 जुलाई 2024 तक शालीमार से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 04 से 06 जुलाई 2024 तक पुणे से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिन्द एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 06

से 08 जुलाई 2024 तक हावड़ा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12130 हावड़ा-पुणे आजाद हिन्द एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 04 जुलाई, 2024 को पोरबंदर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 06 जुलाई, 2024 को शालीमार से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12906 शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दिनांक 06 जुलाई, 2024 को उदयपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 20971 उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दिनांक 07 जुलाई, 2024 को शालीमार से रवाना होने वाली गाडी संख्या 20972 शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दिनांक 05 जुलाई, 2024 को पोरबंदर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12949 पोरबंदर-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दिनांक 07 जुलाई, 2024 को सांतरागाछी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12950 सांतरागाछी-पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दिनांक 06 जुलाई, 2024 को कामाख्या से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22512 कामाख्या-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दिनांक 09 जुलाई, 2024 को एलटीटी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22511 एलटीटी-कामाख्या एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दिनांक 06 जुलाई, 2024 तक एलटीटी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12101 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 08 जुलाई, 2024 तक शालीमार से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12101 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

देरी से रवाना होने वाली गाडियां-

दिनांक 30 जून 2024 को पुणे से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिन्द एक्सप्रेस 30 मिनिट देरी से रवाना होगी। दिनांक 01 जुलाई, 2024 को हावड़ा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12130 हावड़ा-पुणे आजाद हिन्द एक्सप्रेस 01 घंटे 30 मिनिट देरी से रवाना होगी। दिनांक 30 जून 2024 को ओखा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22905 ओखा-शालीमार एक्सप्रेस 01 घंटे देरी से रवाना होगी। दिनांक 01 जुलाई, 2024 तक एलटीटी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12101 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस 01 घंटे 30 मिनिट देरी से रवाना होगी। दिनांक 05 जुलाई, 2024 तक एलटीटी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12101 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस 02 घंटे 30 मिनिट देरी से रवाना होगी

बच्चे के अपहरण और हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

कबीरधाम। कबीरधाम जिला कोर्ट ने 9 वर्ष के बालक हिमांशु उर्फ डोनेश राणा हत्याकांड मामले में बुधवार को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बिडोरा का है, जहां आरोपियों ने 26 दिसंबर 2019 को 30 लाख रुपए फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी थी।

लोक अभियोजक संतोष कुमार देवांगन ने बताया कि धारा 363, 302, 120बी, 201, धारा 3 (2) (ङ्क) एट्रोसीटी एक्ट के तहत आरोपी यशवंत पाली, पिता रमेश पाली उम्र 21, कोमल उर्फ छोटू पाली पिता दिलीप पाली उम्र 19, हेमंत पाली पिता गणेश पाली उम्र 19 को आजीवन कारावास व प्रत्येक धाराओं में 500- 500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।

मृतक हिमांशु 26 दिसंबर 2019 को घर से बैडमिंटन खेलने निकला था। शाम तक घर वापस नही आने के बाद परिजनों ने थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच के दौरान घटना के

करीब 35 दिन बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब तीनों ने हिमांशु का अपहरण कर हत्या कर उसके शव को ग्राम टाटावाही जंगल के गड्ढा में छिपाने की बात कही थी।

पता चला कि हिमांशु के अपहरण के बदले 30 लाख रुपए वसूल करना था। इसी उद्देश्य से हिमांशु का अपहरण किया। हत्या कर उसके शव को बोरी में भरकर तथा कंबल से लपेटकर बाइक से सुनसान रास्ता होते हुए ग्राम टाटावाही गांव के बाहर गड्ढा में छिपा दिया था। यह घटना जिले में काफी चर्चित रही। घटना के करीब 35 दिन बाद आरोपी पकड़े गए थे।

सिर्फ डिग्री की गिनती के फेर में न रहे, काबिलियत के लिए पढ़ें- वित्त मंत्री चौधरी

संकल्प मजबूत होंगे तो विकल्पों की कमी नहीं होगीः ओपी

रायपुर। सिर्फ डिग्री पा लेना और उसकी संख्या बढ़ाना आपको कामयाबी के मुकाम तक नहीं लेकर जायेगा, स्किलफुल बनेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए गिनती के फेर में न पड़ें और काबिलियत के लिए पढ़ें, वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने आज करियर काउंसलिंग के दौरान बच्चों को यह सलाह दी। वे आज स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बीच उन्हें करियर संबंधी मार्गदर्शन देने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 'उत्कर्ष-भविष्य का निर्माण' कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्हें सुनने बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ शिक्षक और पालक भी पहुंचे थे।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने एक घंटे के अपने संबोधन में छात्रों को अपनी अब तक जीवन अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि एक छोटे से गांव से निकल कर देश के प्रतिष्ठित आईएएस सेवा में चयन, प्रशासनिक करियर से लेकर राजनीतिक जीवन में प्रवेश और अब प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने का सफर कैसा रहा, क्या चुनौतियां रहीं, उनसे कैसे निपटे और भविष्य के लिए और बड़े लक्ष्य कैसे तय किए और उन्हें कैसे पूरा किया।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि 11 साल की उम्र में अपनी मां के साथ जब रायगढ़ के कलेक्टर ऑफिस पहली बार आया था तभी से मन में ठान लिया था कि आगे चल कर आईएएस बनना है। इस सपने को मैंने जिया, लगातार मेहनत की और 23 साल की एज में सबसे कम उम्र में से एक आईएएस बनने की उपलब्धि हासिल हुई। उन्होंने कहा कि बायंग गांव से निकल कर जब मैं आईएएस बन सकता हूं जिसके पिता का देहांत 8 वर्ष की उम्र में हो गया था और मां सिर्फ चौथी तक पढ़ी है तो आप में से हर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है। बशर्ते आपको परिस्थितियों से हारना या घबराना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। संकल्प यदि मजबूत होगा तो विकल्पों की कमी नहीं होगी।

हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं जो बताते हैं कि विषम परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले सफलता की नई इबारत लिखते हैं। उन्होंने विराट कोहली के पिता के निधन के दिन अपनी टीम के लिए खेली गई बहुमूल्य पारी, आनंद कुमार के संघर्षों के बारे बताते हुए कहा कि इन सभी सफल लोगों ने कठिन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नही दिया बल्कि उससे लड़े और जीते।

उन्होंने बताया कि आईएएस की नौकरी छोडऩे के बाद कृषि कार्य और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम सीखा। खेती-किसानी के वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान लिया, रिसर्च किया, एग्रोनॉमिक्स विशेषज्ञों से सीखने की कोशिश की जिसका पूरा लाभ आज उन्नत कृषि में ले रहा हूं। यह सब बताने के पीछे का अर्थ यह है कि आप समझ लें कि जो करना चाहते हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान लीजिए, एक्सपर्ट से सीखिए उसे अप्लाई कीजिए फिर कमाल देखिए। अंत में उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता प्रयासों लेना दो ही परिणाम हो सकते हैं। असफल होने पर निराश नहीं होना है। कोई अनुचित कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जिंदगी किसी एक एग्जाम, किसी एक प्रयास से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक अप्रोच रखें। उन्होंने कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल और सीईओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित करियर गाइडेंस सेमिनार की सराहना की और कहा कि इस कार्यक्रम का नियमित आयोजन किया जाए जिससे छात्रों से संवाद बना रहे।

कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने भी बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों से अपने समय का सदुपयोग करने और देश के भविष्य में अपना योगदान देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह समय महत्वपूर्ण है इसमें की गई मेहनत के जो परिणाम मिलते हैं उसका असर पूरे जीवन की दशा दिशा तय करते हैं।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव, श्री गुरूपाल भल्ला, श्री मुकेश जैन, श्रीकांत सोमावार, श्री सुभाष पाण्डेय, श्री विवेक रंजन सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम श्रीमती पूनम सोलंकी, शोभा शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से मिले 1 घंटे बाद मनीराम के हाथों में आ गया दिव्यांग प्रमाण पत्र

रायपुर। धरसींवा निवासी श्री मनीराम देवांगन का चार महीने पूर्व एक्सीडेंट हुआ था। उसमें इनका पैर काटना पड़ गया था। मनीराम पिछले एक महीने से दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे थे लेकिन उनके आवेदन पर कारवाई नहीं हो सकी थी। मुख्यमंत्री जनदर्शन की जानकारी होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या रखने की बात सोची। मुख्यमंत्री को उन्होंने संबंध में जानकारी दी।मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की निर्देश दिए। एक घंटे के भीतर मनीराम के हाथ में दिव्यांगता प्रमाण पत्र आ गया। मनीराम ने खुशी जताते हुए कहा कि दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात वो शासन की दिव्यांगजनों के लिए दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। साथ ही वह कृत्रिम पैर भी लगा पाएगा। जिसके चलते परिवार को संभालने की महती जिम्मेदारी पूरी कर सकेगा। मनीराम ने कहा कि उसे लगा था कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर कुछ दिनों में उसका प्रमाण पत्र बन जाएगा लेकिन उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि एक घंटे प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।

कैंसर पीड़ित पति के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से मांगी सहायता

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जनदर्शन में मुख्यमंत्री के पास बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए। मुख्यमंत्री ने बारी-बारी से सभी के आवेदन देखें और त्वरित कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। जनदर्शन में एक महिला अपने पति श्री रमेश शुक्ला की समस्या लेकर आई। पत्नी ने बताया कि उनके पति श्री शुक्ला कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी की वजह से उन्हें एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने महिला को संबल देते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है। आपके पति को सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रीमती शुक्ला ने आभार जताते हुए कहा कि हम लोग जनदर्शन में बहुत उम्मीद लेकर आए थे। आप से मिलकर, मुझे अपने पति के जल्द इलाज और गुणवत्तापूर्ण इलाज का भरोसा मिला है आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के संबंध में चर्चा में श्रीमती शुक्ला ने बताया कि 2 दिन पूर्व जन दर्शन की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था कि सांसद और मंत्री रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों का इलाज कराया है। जनदर्शन में इसका मौका मिला तो मैं आई। मेरा यहां आना सफल हुआ है।

युवती ने कहा सहायक अध्यापक में 7 साल से नहीं मिल रही नियुक्ति

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जनदर्शन में गुढिय़ारी से बबीता पांडे और उनके पिता आवेदन लेकर आए। उन्होंने बताया कि 7 साल पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आदेश किया गया था। इसके बावजूद भी अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकरण की जांच उच्च शिक्षा विभाग से कराएंगे और नियमानुसार इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। बबीता पांडे के साथ उनके पिता भी आए थे। पिता ने कहा कि मेरी बिटिया जूलॉजी विषय से पीएससी परीक्षा में शामिल हुई थी। 7 साल पहले रिजल्ट आया और बिटिया पास हुई। हमें बहुत उम्मीद थी कि शीघ्र ही नियुक्ति मिल जाएगी। हमने इसका इंतजार किया लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाई। हम लोग कोर्ट में भी गए। कोर्ट ने हमें राहत मिली लेकिन हमारे प्रकरण पर कार्रवाई नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि आश्वस्त रहें। प्रकरण पर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम में आए दिव्यांगजनों के प्रति दिखाई संवेदनशीलता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जनदर्शन कार्यक्रम में आए दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे दिव्यांगजनों की जांच कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य जांच के उपरांत दिव्यांगजनों की जरूरत के अनुसार उन्हें ट्राइसाइकिल और श्रवण यंत्र भी वितरित किए।

आर्चरी में ओलंपिक खेलने का सपना है अंकिता का

रायपुर। मुख्यमंत्री जनदर्शन में आज चरोदा से आई अंकिता मौर्य मुख्यमंत्री के पास आवेदन लेकर पहुंची। उन्होंने बताया कि वे आर्चरी की खिलाड़ी हैं। वे खेलो इंडिया खेलों में ब्रांज मेडल जीत चुकी हैं। उनका सपना ओलंपिक खेलने का है उनका किट काफी पुराना हो गया है यदि नया किट उपलब्ध करा दिया जाए तो उनका सपना पूरा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों की प्रतिभा को आगे बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके प्रकरण को खेल विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। आपका सपना पूरा हो इसके लिए आपको हर संभव सहायता दी जाएगी। अंकिता ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ध्यान से मेरी बात सुनी और सपना पूरा करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। दो दिन पहले ही मुझे मुख्यमंत्री जनदर्शन की जानकारी मिली थी। मैंने देखा था कि मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में मलखंभ के खिलाडिय़ों को बहुत प्रेरित किया था। मुझे लगता था कि मैं अपने सपने को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी तो इसे जरूर पूरा करेंगे आज मुझे बहुत संतोष महसूस हो रहा है।

किसी को व्हीलचेयर, तो किसी को मिला कृत्रिम पैर

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास में आज से प्रारंभ हुए साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से निःशक्तजनों ने भी मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराते हुए अपने लिए सहायक उपकरण की मांग की। मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी समस्याओं को सुना बल्कि संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांगजन को मौके पर ही व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्रायसायकल, कृत्रिम पैर, बैटरी चलित सायकल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल गए, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया। जनदर्शन कार्यक्रम में तहसील लोरमी, जिला मुंगेली निवासी दिव्यांग अजय सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री श्री साय को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मेरा एक पैर कट जाने के कारण कृत्रिम पैर लगाया गया था, जो अब खराब हो गया है। मुझे एक नया कृत्रिम पैर की जरूरत है। मुख्यमंत्री द्वारा उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया गया, उनके निर्देश पर दिव्यांग अजय सिंह राजपूत के पैर का माप लिया गया। कृत्रिम पैर बनने के बाद उन्हें कृत्रिम पैर प्रदान किया जाएगा। जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे रायपुर शैलेन्द्र नगर निवासी कु. केसर चंदवानी के अभिभावक ने बताया कि मेरी पुत्री कु. केसर चंदवानी जिसकी उम्र 11 वर्ष है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेरी पुत्री के ईलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाए।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल से एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियन श्रीमंत ने सौजन्य मुलाकात की

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से गुरुवार को राजभवन में एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल विजेता श्री श्रीमंत झा ने सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने उनकी उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि श्री श्रीमंत ने देश एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। राज्यपाल ने उन्हें मेडल पहनाया और बधाई दी साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के पैरा-आर्म पहलवान श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा-आर्म रेसलिंग चैपियनशिप 2024 में 85 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता साथ ही माल्डोवा (यूरोप) में आयोजित होने वाले आगामी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए चयनित हुए हैं।

महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का साप्ताहिक जनदर्शन आज से प्रारंभ हो गया है। आज पहले ही दिन प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आए आम नागरिकों एवं विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों ने सौजन्य मुलाकात कर मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। जनदर्शन में मुख्यमंत्री सहज रूप से सभी से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन ले रहे हैं। माताओं एवं बहनों के समूह ने महतारी वंदन योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रूपए मिलने से उनकी हर छोटी-बड़ी समस्या दूर हो रही है। इस राशि से बहने अपने बच्चों की आवश्यक जरूरतों को भी पूरी कर रही है। महतारी वंदन योजना से माताओं एवं बहनों को आर्थिक रूप से संबल मिला है।

सैम पित्रोदा को फिर से पद देने वाली कांग्रेस का देशविरोधी चेहरा उजागर: कश्यप

■ **पुरखो की संपति में 55 प्रतिशत टैक्स लगाने की सलाह देने वाले, भारत के लोगो पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को कांग्रेस ने फिर से पद क्यों दिया**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने सेम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पर पुनः बहाल किए जाने पर तीखा हमला बोला है। श्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के इस फैसले से कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र बेनकाब हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान विरासत टैक्स लगाने, रंगभेद आदि से जुड़े बयानों के मद्देनजर पद से हटाए गए राहुल गांधी के सलाहकार पित्रोदा को हटाया गया था, लेकिन अपने इस फैसले से पलटकर कांग्रेस नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए देश के लोग नही सैम अंकल प्राथमिकता रखते है।पित्रोदा की बहाली ने कांग्रेस की उस विकृत राजनीतिक मानसिकता को भी साफ कर दिया है कि विरासत टैक्स, रंगभेद जैसे बयान कांग्रेस की सोची- समझी साजिशाना रणनीति के तहत दिए गए या दिलाए गए, और विवाद के चलते वोट बैंक के डैमेज कंट्रोल के लिहाज से पित्रोदा को हटाने का काम किया लेकिन अब यह आईने की तरह

साफ हो गया है कि ये बयान कांग्रेस का आधिकारिक स्टैण्ड ही है।

कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के तमाम बयान बहुत ही सोचे-समझे होते हैं ताकि समाज में अलगाव और घृणा फैले। ये बयान चुनावी नफे-नुकसान को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, फिर दिखावे के लिए कार्रवाई करने के बाद निर्लज्जतापूर्वक पद पर बहाल किया जाता है। श्री कश्यप ने कहा कि पित्रोदा की तरह ही, जज बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म करते कैमरे में कैद हुए अभिषेक मनु सिंघवी को प्रवक्ता पद पद से से हटाने के बाद फिर उन्हें प्रवक्ता बना दिया गया। कांग्रेस के ये तमाम राजनीतिक फैसले देश की गरिमा, लोकतांत्रिक व सामाजिक मर्यादा पर गहरी चोट करने वाले हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए, कम ही है।

नगरीय निकायों और पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दिया जोर

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने कार्यभार ग्रहण करते ही आगामी समय में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियां तेजी से करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने एक अहम बैठक रखी। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन श्री बसवराजू एस. सचिव सामान्य प्रशासन श्री डी.डी. सिंह तथा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे उपस्थित रहे।

बैठक में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करते हुए आयुक्त श्री सिंह ने इसे समय सीमा में कराने पर जोर दिया है। इस मौके पर उन्होंने समय-

समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन से संबंधी दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। बैठक में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए मतदाता सूची की तैयारी की भी आयुक्त श्री सिंह ने समीक्षा की। साथ ही मतदान केन्द्र और मतदान कर्मियों की आवश्यकता और व्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने आम निर्वाचन के पहले सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने पर बल दिया है।

मुख्य सचिव ने कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार यहां मंत्रालय महानदी भवन में नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन भवन के कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, क्रेडा, उद्यानिकी विभाग, संस्कृति विभाग, एनआरडीए और कलेक्टर रायपुर को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को आपसी समन्वय से गुणवत्ता के साथ त्वरित गति से पूर्ण कराएं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से विधानसभा सचिवालय के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीएम के सचिव पी.दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह आदि शामिल हुए।

निविदा के बाद अब तुरंत काम होगा शुरू

■ **पीडब्लूडी ने जारी किए नए दिशा-निर्देश**

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूर्ण करने राज्य शासन द्वारा निविदा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सड़क और सेतु निर्माण के लिए निविदा के पहले संबंधित कार्यपालन अभियंता को प्रमाणित करना होगा कि कार्य के लिए 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण के लिए पूरी जमीन व्यवधानरहित होने पर ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव द्वारा विभागीय कार्यों में तेजी और कसावट लाने के निर्देश के बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता सहित सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र

जारी किया गया है। विभाग ने नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इनका समुचित पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मंत्रालय से प्रमुख अभियंता से लेकर सभी कार्यपालन अभियंताओं को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि सड़क निर्माण के लिए सड़क की प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में में पूर्ण कर ली जाएगी। विभाग ने भवन निर्माण के लिए 100 प्रतिशत व्यवधानरहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि सेतु कार्यों के पहुंच मार्ग के लिए 90 प्रतिशत लंबाई बाधारहित होने पर ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाए। निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि पुल निर्माण हेतु पुल के पहुंच मार्ग के लिए प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में में पूर्ण कर ली जाएगी। विशेष प्रकरणों में शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

जनदर्शन में किसान के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर रकम निकालने का मामला पहुंचा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जनदर्शन कार्यक्रम में आम जनता से संबंधित शिकायतों एवं अपेक्षाओं के कई तरह के मामले देखने और सुनने को मिल रहे हैं। जनदर्शन में लोग मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे हैं और अपनी अपेक्षाओं से संबंधित आवेदन भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज शुरू हुए जनदर्शन कार्यक्रम में किसान ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि उसके सहकारी बैंक के खाते से फर्जी तरीके से न सिर्फ राशि निकाली गई है, बल्कि उनके नाम से फर्जी तरीके से केसीसी लोन भी निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने किसान ओम प्रकाश की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर के कलेक्टर को तत्काल मामले की जांच कराने तथा दोषी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के साथ ही किसान को राशि वापस कराने के भी निर्देश दिए।

जनदर्शन कार्यक्रम में जिला बिलासपुर, थाना सीपत के ग्राम नवागढ़ के किसान श्री ओमप्रकाश ने बताया कि उसके सहकारी बैंक खाते से रमेश साहू, जो कि सेवा सहकारी समिति सीपत में कम्प्यूटर ऑपरेटर है, उसने फर्जी हस्ताक्षर कर तीन बार में कुल 27 हजार रूपए निकाल लिए हैं। विड्रॉल पर्ची निकालने पर पता चला कि रमेश साहू ने उसके नाम का फर्जी हस्ताक्षर कर रकम निकाली है। रमेश साहू ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर उससे बैंक पासबुक ले लिया और फर्जी तरीके से राशि आहरित की। किसान ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि उसके नाम पर किसी ने फर्जी तरीके से वर्ष 2019 में 16 हजार रूपए का लोन भी निकाला है।

भाजपा के सामने सत्ता के बंटवारे की चुनौती

हरीश गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकल खिलाड़ी और अपने काम में दक्ष माना जाता है। मोदी ने एक नई कार्यसंस्कृति लाकर पूरे देश में जोश पैदा किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 13 साल के कार्यकाल के दम पर ही वे 2014 के लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत पाने वाले 30 साल में पहले नेता बने। उन्होंने 2019 में अपनी सीटों की संख्या में और सुधार किया और 303 सीटें जीतकर भाजपा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन 2024 में 'ब्रांड मोदी' को बड़ा झटका लगा और भाजपा 240 लोकसभा सीटों पर सिमट गई। बेशक, मोदी ने 293 सांसदों के साथ गठबंधन सरकार बनाई। लेकिन भाजपा अभी भी इनकार की मुद्रा में है और ऐसा दिखा रही है जैसे मोदी 2.0 और मोदी 3.0 सरकारों में कोई अंतर नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी शुरुआती दिन हैं और मोदी 2.0 और मोदी 3.0 सरकारों के बीच अंतर को समझने में समय लगेगा। भाजपा के सहयोगी दल भी अपने-अपने मामलों को सुलझाने में व्यस्त हैं। हालांकि, उनमें से कई ने पिछले 10 वर्षों के दौरान मोदी सरकार की कार्यशैली का स्वाद चखा है। वे जानते हैं कि इस अवधि के दौरान भाजपा ने अपने सहयोगियों और अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। लेकिन उन्होंने अपने हितों के मुद्दों पर बात करना शुरू कर दिया है। जल्द ही राज्यपालों, आयोगों और न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों और सदस्यों, सार्वजनिक उपक्रमों में निदेशकों आदि की नियुक्तियों में अपना हिस्सा मांगेंगे। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान, मोदी सरकार ने ऐसी नियुक्तियों में आरएसएस के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी थी। भाजपा पर अपने सहयोगियों के साथ सत्ता को साझा करने का दबाव होगा। भाजपा ने भले ही लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर इतिहास रच दिया हो, लेकिन उसे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए 2024 में फिर से परीक्षा पास करनी होगी। पार्टी ने बहुत कुछ खो दिया है और उसकी अजेयता पर सवालिया निशान लग गया है क्योंकि वह 240 लोकसभा सीटें जीतकर बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई। अपना दबदबा फिर से हासिल करने के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में तीन में से कम से कम दो विधानसभा चुनाव जीतने होंगे। हालांकि जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, लेकिन सरकार अन्य तीन राज्यों में इसी तरह की कवायद करने से पहले इसे कराने पर विचार कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा इन तीनों राज्यों में शासन कर रही है और लोकसभा के चौंकाने वाले नतीजों से पहले उसका प्रदर्शन मजबूत था। भाजपा और उसके सहयोगी महाराष्ट्र और हरियाणा में अपना दबदबा बनाए रखने में बुरी तरह विफल रहे और झारखंड में बमुश्किल लोकसभा की अधिकांश सीटें जीत पाए। महायुति ने अधिकांश लोकसभा सीटें खो दीं और तीनों सहयोगियों, भाजपा-शिवसेना-राकांपा के बीच काफी अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं। भाजपा के लिए एकमात्र अच्छी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना (यूबीटी) गुट अब हिंदुत्ववादी ताकतों का मसीहा नहीं रह गया है क्योंकि वह शरद पवार और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है जो राज्य में 'धर्मनिरपेक्ष' ताकतों का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। इसी तरह, हरियाणा में भी भाजपा के सामने एक समस्या है, जहां वह दस साल से सत्ता में है। लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद वह दस में से पांच लोकसभा सीटें हार गई और दो सीटें बहुत कम अंतर से जीत पाई। भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस छोटे से राज्य से तीन केंद्रीय मंत्री बनाए हैं। झारखंड में, भाजपा को फिर से उभर रहे इंडिया गठबंधन का सामना करना पड़ेगा, हालांकि उसने 14 में से 9 सीटें जीती हैं। इन राज्यों में कोई भी प्रतिकूल परिणाम एनडीए गठबंधन में और अधिक अनिश्चितताएं पैदा करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार बार राज्यसभा सांसद रहे जयराम रमेश ने इस आम चुनाव में मीडिया रणनीति को बखूबी संभालकर अपनी योग्यता साबित की और कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख के रूप में अपने संचार कौशल का परिचय दिया।

बिरला के अध्यक्ष बनने से शुरुआत सही दिशा में

ललित गर्ग

ओम बिरला को दूसरी बार ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनिमत पर विपक्ष ने डिविजन की मांग नहीं की। ओम बिरला के नाम पर विपक्ष का विरोध न करना मोदी सरकार के लिए भी किसी आश्चर्य से कम नहीं रहा। उम्मीद यही की जा रही थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग करेगा और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा। ओम बिरला को नये लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की खूबसूरती की छटा बिखेर रही थी, वहीं ऐसी संभावनाओं को बल दिया कि अठाहरवीं लोकसभा के सभी सत्र एक नया इतिहास का सृजन करते हुए उम्मीदभरे होंगे। कोटा से तीसरी बार के सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। वे लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले तीसरे शख्स हैं। उनसे पहले बलराम जाखड़ 9 सालों तक स्पीकर रहे थे। ओम बिरला का चुना जाना चौंकाता नहीं है, बल्कि जो बात थोड़ी हैरान करने वाली थी वह है इस पद के लिए चुनाव की नौबत लाया जाना। वैसे तो लोकतंत्र में चुनाव किसी भी पद के लिए हो, उसे बुरा मानने का कोई कारण नहीं है। मगर लोकसभा अध्यक्ष का पद ऐसा है जिसमें आम राय को हमेशा तवज्जो दी जाती रही है। वजह यह है कि सदन के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष को दोनों पक्षों का सहयोग चाहिए होता है। ऐसे में अगर इस पद पर बैठे व्यक्ति का चयन दोनों पक्ष उसमें अपना विश्वास घोषित करते हुए करें तो पद की शोभा कई गुना बढ़ जाती है।

स्वतंत्र भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए केवल तीन बार 1952, 1967 और 1976 में चुनाव हुए। वर्ष 1952 में कांग्रेस सदस्य जी. वी. मावलंकर को लोकसभा स्पीकर के रूप में चुना गया था। लोकसभा अध्यक्ष पद पर चयन को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से चुनाव की नौबत आ गई। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन के बाद सरकार और विपक्ष के बीच

यह पहला शक्ति प्रदर्शन था। इसलिए भाजपा के रणनीतिकार अपने उम्मीदवार ओम बिरला को ज्यादा से ज्यादा सांसदों के समर्थन के साथ बड़ी जीत दिलवाने के मिशन में जुट गई थी। इंडिया गठबंधन की पूर्व रात्री को हुई बैठक में ही नेताओं का कहना था कि इंडिया गठबंधन के पास संख्या बल नहीं है। इसलिये बिना मतदान के ही ध्वनिमत से बिरला के अध्यक्ष चुने जाने की कार्रवाई को निर्बाध होने दिया एवं संसदीय पटल पर खुशी का माहौल दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बधाई देते हुए संविधान रक्षा की बात दोहरायी। सदन में तीसरे सबसे बड़े दल के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवाशाली परंपरा जुड़ी है। इसलिए सबकुछ बिना भेदभाव आगे बढ़ेगा। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं।'

हर राष्ट्र का सर्वोच्च मंच उस राष्ट्र की पार्लियामेंट होती है, जो पूरे राष्ट्र के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, राष्ट्र-संचालन की रीति-नीति और नियम तय करती है, उनकी आवाज बनती है व उनके ही हित में कार्य करती है। राष्ट्र के व्यापक हितों की सुरक्षा करती है। भारत का लोकतंत्र न केवल सशक्त है बल्कि अनूठा एवं प्रेरक है, उसका सर्वोच्च मंच लोकसभा है। सत्रहवीं लोकसभा के सत्रों की कार्यवाही बिरला ने नियोजित एवं सुचारू ढंग से संचालित कर एक स्वस्थ परम्परा का सूत्रपात किया था, उनके अनुभव एवं क्षमताएं सदन को नई दृष्टि देने के लिए तत्पर रहे हैं। उनके सदन संचालन की दक्षता एवं कौशल की ताजी हवा के झोंकों का अहसास देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक सदन लोकसभा महसूस करता रहा है। वे लोकसभा को कुशलता से संचालित करने में न केवल खरे उतरे हैं बल्कि नये प्रतिमान स्थापित करते हुए सदन की गरिमा एवं गौरव की अभिवृद्धि की हैं। अठारहवीं लोकसभा के अध्यक्ष बनकर निश्चित ही वे सदन की कार्यवाही को अनुशासित भी कर सकेंगे, अनुप्रेरित भी कर सकेंगे और पक्ष-विपक्ष के बीच संतुलन रखते हुए देशहित में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे, ऐसा विश्वास है। निश्चित ही निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए सदन की गरिमा को नए स्तर तक ले जाने में वे सक्षम साबित होंगे।

लोकसभा कुछ खम्भों पर टिकी एक सुन्दर ईमारत ही नहीं है, यह एक अरब चालीस करोड़ जनता के दिलों की धड़कन है। उसके एक-एक मिनट का सदुपयोग हो। वहां शोर, नारे और अव्यवहार न हो, अवरोध पैदा नहीं हो। ऐसा होना निर्धनजन और देश के लिए हर दृष्टि से महंगा सिद्ध होता है। यदि हमारे प्रतिनिधि ईमानदारी से नहीं सोचेंगे और आचरण नहीं करेंगे तो इस राष्ट्र की आम जनता सही और गलत, नैतिक और अनैतिक के बीच अन्तर करना ही छोड़ देगी। निश्चित ही संतुलन, निष्पक्षता, शालीनता एवं कौशल के बल पर बिरला नये लोकसभा के सदन की कार्रवाई को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे और नयी उम्मीदों को पंख लगायेंगे। इसमें पक्ष एवं विपक्ष का सहयोग अपेक्षित है तभी लोकसभा की शालीनता एवं सभ्यता नई ऊंचाइयों पर आरोहण करेंगी। देश का भविष्य संसद के चेहरे पर लिखा होता है, यदि वहां मर्यादाहीनता एवं अशालीनता का प्रदर्शन होता है तो समस्याएं सुलझने की बजाय उलझती जाती है। छोटी-छोटी बातों पर अभद्र शब्दों का व्यवहार, हो-हल्ला, छींटाकशी, हंगामा और बहिर्गमन आदि ऐसी घटनाएं है, जिनसे संसद जैसी प्रतिनिधि संस्था का गौरव घटता है। यह बात चुने हुए प्रतिनिधियों को समझाने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने में बिरलाजी ने पूर्व में जिस तरह की सिद्धहस्तता का परिचय दिया है, वह काबिलेतारीक है।

संसद करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कर उनकी आवाज बनती हैं। हमारे राष्ट्र की लोकसभा का यही पवित्र दायित्व होता है कि वह उसकी पवित्रता एवं स्वस्थता कायम रखे तथा सभी प्रतिनिधि भगवान् और आत्मा की साक्षी से इस दायित्व को निष्ठा व ईमानदारी से निभाने की शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद पर केवल लम्बे संसदीय अनुभव रखने वाले सांसद का चुनाव जरूरी नहीं होता। देखना यह होता है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है अथवा नहीं और वह सभी पक्षों के साथ यथोचित न्याय करने का हौंसला रखता है या नहीं। सदन में जब मूल्य एवं नैतिक मानक कमजोर हो जाते हैं और सिर्फ निजी हैसियत को ऊँचा करना ही महत्त्वपूर्ण हो जाता है तो वह सदन निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। आजादी के अमृत काल में भी हम अपने आचरण और काबिलीयत को एक स्तर तक ऊंचा उठाये। नेता और नायक किसी कारखाने में पैदा करने की चीज नहीं हैं, उनकी काबिलीयत और चरित्र को गढ़ने का काम भी लोकसभा ही करती है। संविधान की शब्दधाराओं को ही नहीं उसकी भावना को महत्व देने के गुणों का विकास भी यहीं से होता है। बोलने की आजादी का सदुपयोग करना भी यही पर सिखाया जाता है। नये अध्यक्ष लोकसभा को प्रशिक्षण की प्रयोगशाला बनाये। नई लोकसभा अपने भीतर ऐसे परिवेश को जन्म दे, जो स्वयं आगे आकर नवनिर्माण करें, दायित्व की बागडोर थामे और सुधार, स्वस्थता एवं विकास का कार्य शुरू करें। लोकसभा बड़े आदर्शों की अपेक्षा एक छोटा-सा सवाल अपने आपसे करने की कोशिश कर रही है कि नयी लोकसभा की अगवानी में अलविदा किसे कहे? अतीत के उन घटना-प्रसंगों को अलविदा कहें जिनकी वजह से लोकसभा के सपने एवं संकल्प अधूरे रहे और उसकी गरिमा धूमिल होती रही है। शुरुआत तो अच्छी हो रही है देखिये आगे क्या होता है? इतना तो है ही कि इस बार सभी पक्षों से बेहतर समझदारी और परिपक्वता की अपेक्षा रहेगी।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

सुबालोपनिषद् (भाग-21)

गतांक से आगे...

तत्पश्चात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश को दग्ध करता है, इसके बाद जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, महानता के लोक तथा परलोक को भी दग्ध कर देता है, तदनन्तर लोक एवं अलोक को दग्ध करता है, धर्म एवं अधर्म को दग्ध करता है, तत्पश्चात् बिना सूर्य के, बिना मर्यादा के और बिना आलोक के वह सभी स्थलों को दग्ध कर देता है, उसके बाद महत्तत्त्व को दग्ध कर देता है, प्रकृति को दग्ध करता है, अक्षर को दग्ध करता है तथा मृत्यु को भी दग्ध कर देता है। मृत्यु ही . परमादिदेव परमतत्त्व में एकाकार हो जाती है, उसके बाद न सत् है, न असत् और न ही सत-असत् है।

यही निर्वाण (मुक्ति) का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है, यही वेद का अनुशासन है। सौबाल (सुबाल सम्बन्धी) जिस ब्रह्म का बीज है, ऐसे इस उपनिषद् को अन्य किसी को नहीं प्रदान करना चाहिए, जो अत्यधिक शान्त न हो, जो पुत्र न हो, जो शिष्य न हो तथा जो एक वर्ष तक पास में न रहा हो।

इस प्रकार से अनजान कुलशील वाले मनुष्य को भी नहीं प्रदान करना चाहिए और न ही उसे बताना चाहिए। जिस व्यक्ति की परमात्मशक्ति के ऊपर तथा परमात्मा के सदृश ही गुरु के ऊपर परम श्रेष्ठ भक्ति हो, उसी के लिए ये अर्थ (विशेष ज्ञान) बतलाये गये हैं तथा ऐसे ही महान् आत्मा को ये प्रकाशित करते हैं। यही निर्वाण (मुक्ति) का आदेश है, यही वेदों की शिक्षा है तथा यही वैदिक अनुशासन है।

दानवीर भामाशाह

विजय राम

राजस्थान की धरा अनेक वीर सपूतों की जननी है। यहां आज ही के दिन भामाशाह का जन्म हुआ था। भामाशाह वो नाम है, जो यहां आदर से लिया जाता है। उनके नाम से सरकारी योजनाएं चल रही हैं। और दानवीरों की बात आती है तो भी उनका नाम जुबां पर आ जाता है। वह सैकड़ों बरस पहले महाराणा प्रताप के समय जन्मे थे। कहा जाता है कि, भामाशाह ने प्रताप के लिए अपनी सारी जमा-पूंजी अर्पित कर दी थी।

वो दौर जब मुगलों के हमले हो रहे थे तो भामाशाह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अपना सब-कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने दूजों की भलाई के लिए जीवनभर दान किया। ऐसे दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में 28 जून, 1547 को हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि, उनके पिता भारमल्ल तथा माता कर्पूरदेवी थीं। भारमल्ल राणा साँगा के समय रणथम्भौर के किलेदार थे। अपने पिता की तरह भामाशाह भी राणा परिवार के लिए समर्पित थे।

मुगल बादशाह अकबर से लोहा लेते हुए जब महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि का त्याग करना पड़ा तो वे अपने परिवार सहित जंगलों में रहने लगे। महलों में रहने और सोने चाँदी के बरतनों में स्वादिष्ट भोजन करने वाले महाराणा के परिवार को उन दिनों अपार कष्ट उठाने पड़ रहे थे। राणा को बस एक ही चिन्ता थी कि किस प्रकार फिर से सेना जुटाएँ, जिससे मेवाड़ को आक्रांताओं से चंगुल से मुक्त करा सकें। उस समय राणा के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या धन की थी। उनके साथ जो विश्वस्त सैनिक थे, उन्हें भी काफी समय से वेतन नहीं मिला था। कुछ लोगों ने राणा को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, लेकिन राणा जैसे देशभक्त एवं स्वाभिमानी को यह कतई मंजूर नहीं था।

महाराणा प्रताप के कष्टों के बारे में जब भामाशाह को पता चला तो उनका दिल दहल उठा। भामाशाह ने मदद की ठानी। उनके पास स्वयं का धन और पुरखों की वसीयत थी। उन्होंने वो सब महाराणा प्रताप को अर्पित कर दिया। इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि, राणा के लिए भामाशाह ने 25 लाख रुपए की नकदी तथा 20,000 अशर्फी दीं। तब राणा ने आँखों में आँसू भरकर भामाशाह को गले से लगा लिया। वहीं, राणा की पत्नी महारानी अजवान्दे ने भामाशाह को पत्र के जरिए इस सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त की।

भामाशाह महाराणा प्रताप की महारानी के सम्मुख उपस्थित हुए और नम्रता से कहा कि, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। यह सब धन मैंने देश से ही कमाया है। यदि यह देश की रक्षा में लग जाए, तो यह मेरा और मेरे परिवार का अहोभाग्य ही होगा। महारानी यह सुनकर क्या कहतीं, उन्होंने भामाशाह के त्याग के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। उधर, जब अकबर को यह घटना पता लगी, तो वह भड़क गया। अकबर सोच रहा था कि सेना के अभाव में राणा प्रताप उसके सामने झुक जायेंगे, लेकिन इस धन से तो राणा को नई ताकत मिल गई। चिढ़े हुए अकबर ने क्रोधित होकर भामाशाह को पकड़ लाने को कहा।

नेता प्रतिपक्ष के लिए अगले 60 महीने बड़ा अवसर

विनोद पाठक

संसद में लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक नए अंदाज में दिखे। उन्होंने एक बार फिर सफेद कुर्ता-पजामा पहन लिया। दाढ़ी सलीके से सेट कराई। एक रात पहले उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया था। अपने 20 साल लंबे राजनीतिक करियर में पहली बार राहुल गांधी कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। चूंकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो राहुल गांधी के पास खुद को स्थापित और साबित करने का बड़ा अवसर है। कई बार री-लॉन्च किए जा चुके राहुल गांधी क्या नई जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे? जिन उम्मीदों के साथ जनता ने उनकी पार्टी को 99 सीटें दी हैं, उन पर खरा उतार पाएंगे? इन सवालों के जवाब अगले कुछ महीनों में मिल जाएंगे।

वर्ष 2013 में राहुल गांधी को जयपुर में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में उपाध्यक्ष चुना गया था। तब उन्होंने मार्मिक भाषण दिया था और सत्ता को जहर तक बताया था। कांग्रेस ने उन्हें भविष्य के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया। हालांकि, कांग्रेस वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में अपना सबसे न्यूनतम प्रदर्शन कर 44 सीटों पर सिमट गई थी। तब कांग्रेस ने यह कहकर बचाव किया था कि मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने देशभर में कांग्रेस के प्रचार का नेतृत्व किया, लेकिन पार्टी एक बार फिर बुरी तरह हारी। उसे 52 सीटें मिलीं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के नेतृत्व को जनता ने नकार दिया और राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। वर्ष 2019 के बाद राहुल गांधी कुछ समय के लिए अज्ञातवास में चले गए। पार्टी उनसे नेतृत्व का गुहार लगाती रही, पर काफी मान-मनौव्वल के बावजूद वो नहीं माने।

केंद्र में लगातार 10 साल पूरे कर रही नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर सत्ता विरोधी लहर

का लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी की ओर देखा। करीब-करीब सभी विपक्षी पार्टियों को जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बनाया। यह बात और है कि इस बार विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व किसी एक चेहरे पर नहीं था, क्योंकि कोई भी राहुल गांधी के आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। फिर कुछ क्षेत्रीय दलों की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल और अरविंद केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव में यह साफ कर दिया था कि उनके नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने भी देशभर में जमकर प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की जबरदस्त ब्रांडिंग करती आई है। भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने देश को दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक सड़क से नापा है। वो पिछले कुछ महीनो में सरकार के खिलाफ काफी उत्तेजित नजर आए हैं। बड़ी हुई दाढ़ी, सफेद टी-शर्ट और ब्लैक पेंट, यह उनकी पहचान बन गई थी।

सफेद टी-शर्ट और ब्लैक पेंट के लिए तो उन्होंने यहां तक कहा कि मैं सदा लिबास में रहना पसंद करता हूं। इसलिए सफेद टी-शर्ट पहन लेता हूं। ये और बात है कि इस सफेद टी-शर्ट की कीमत को लेकर सत्ताधारी भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी पर तंज कसा, लेकिन राहुल गांधी इस बार रुकते नहीं दिखे। भले यह तथ्य सही है कि कांग्रेस ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन किया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में 99 सीटें लाकर कांग्रेस अपनी वापसी का डंका बजा रही है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें नहीं ला रही थी तो इस कामयाबी से एक नए उत्साह का संचार उसमें देखने को मिल रहा है।

कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर नजर डाली जाए तो यह साफ दिखता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को अभी से प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की मंशा से आगे बढ़ रही है। उन्हें जननायक बताया जा रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष खड़ा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देने के पीछे कांग्रेस का यही यह गेम प्लान है। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट नजर आ रही है। हालांकि, इन चुनावों में कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली हैं, वो केवल राहुल गांधी के प्रचार या चेहरे की बदौलत नहीं मिली हैं। यह कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी। यहां तक की राजस्थान में कांग्रेस को हनुमान बेनीवाल, भारतीय आदिवासी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा, जहां वो भाजपा से दो-दो हाथ करती है। यह तथ्य भी गौर करने लायक है कि इंडी अलायंस की अधिकांश पार्टियां कांग्रेस की जमीन छीनकर अपने-अपने राज्यों में खड़ी हुई हैं।

राहुल गांधी की असली चुनौतियां अब शुरू हुई है। अब तक वो बिना संवैधानिक जिम्मेदारी के राजनीति कर रहे थे। हालांकि, उनके पास वर्ष 2004 से 2014 के बीच मंत्री और प्रधानमंत्री तक बनने का अवसर था, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, यानी वो कोई संवैधानिक पद लेने से बचते रहे थे। राहुल गांधी के पास अगले 5 साल नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का अच्छा अवसर है। राहुल गांधी इस बार पहले से थोड़े अधिक परिपक्व नजर आ रहे हैं।

लोकसभा के भीतर और बाहर वो थोड़ा फॉर्म में दिखे, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों को थोड़ा संभलकर चलना होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अपनी पहली परीक्षा में राहुल गांधी कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुनने के बजाय उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से प्रत्याशी खड़ा कर दिया, जिसे विपक्ष का प्रत्याशी बताया गया, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जता दी। इंडी अलायंस की एकता में पहली दरार साफ दिखी। जब लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में मत विभाजन का मौका आया तो राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष पीछे हट गया। शायद कांग्रेस को डर था कि जिन 233 सीटें के नंबर को लेकर वो उत्साहित है, वो गुबारा फुस्स न हो जाए। यदि राहुल गांधी सर्वसम्मति पर अध्यक्ष पद के लिए मान जाते तो बहुत संभव था कि डिप्टी स्पीकर का पद वो सरकार से ले लेते, लेकिन अब यह बेहद मुश्किल नजर आता है।

अब राहुल गांधी केवल आरोप-प्रत्यारोप लगाकर राजनीतिक खेल नहीं खेल सकते हैं। उन्हें पूरे तथ्यों और नियमों के साथ सरकार को घेरना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार का एक अल्टरनेटिव जनता के समक्ष पेश करना होगा। राहुल गांधी के पास अगले 60 महीने बहुत बड़ा अवसर होगा। यदि एनडीए गठबंधन सरकार पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा लेती है तो वर्ष 2029 में राहुल गांधी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना सकते हैं।

बड़ा सवाल यह है कि क्या तब तक राहुल गांधी इंडी अलायंस को एकजुट रख पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही होगी कि विपक्षी एकता में दरार पड़े। राहुल गांधी को आगे बढ़ता देख कांग्रेसी जमीन पर खड़ी हुई क्षेत्रीय पार्टियों का रुख क्या रहेगा? यह देखना होगा। इस बार मिले अवसर को राहुल गांधी कितना भुना पाएंगे? इस पर जनता की नजर अवश्य बनी रहने वाली है।

आज का इतिहास

1926 गोतलिब डेमलर और कार्ल बेंज ने कंपनियों को मिलाकर मर्सिडीज-बेंज की स्थापना की।
1942 द्वितीय विश्व युद्ध-जर्मन वेहरमैच ने केस ब्लू लॉन्च किया, सोवियत संघ को अलवर से बाहर खदेड़ने के लिए आक्रामक गर्मियों की शुरुआत की।
1950 कोरियाई युद्ध: उत्तर कोरिया के सैनिकों द्वारा सोल पर कब्जा कर लिया गया था। उत्तर कोरियाई युद्ध में कोरियाई युद्ध उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का युद्ध था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र का बल दक्षिण के लिए लड़ा था, और चीन ने उत्तर के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसे सोवियत संघ द्वारा भी सहायता प्रदान की गई थी।
1956 बेहतर स्थिति की मांग करने वाले श्रमिकों ने पॉन्ना ?, पोलैंड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अगले दिन 400 टैंकों और पोलिश पीपुल्स आर्मी और आंतरिक सुरक्षा कोर के 000 सैनिकों द्वारा हिंसक दमन किया गया।
1965 पहली कमर्शियल सैटेलाइट अर्ली बर्ड ने कम्यूनिकेशन सर्विस शुरू की।
1969 न्यूयॉर्क शहर के स्टोनवेल इन में एक पुलिस छापे के जवाब में, समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों के समूहों ने न्यूयॉर्क शहर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंगा करना शुरू कर दिया, जो दुनिया भर में समलैंगिकता आंदोलन के लिए एक वाटरशेड घटना थी।
1972 अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषणा की, कि वियतनाम को कोई नया प्रारूप नहीं भेजा जाएगा।
1976 अमेरिका के एयरफोर्स एकेडमी में पहली महिला का प्रवेश हुआ।
1981 तेहरान में पार्टी के मुख्यालय में बम विस्फोट होने पर ईरान के इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के तीन प्रमुख अधिकारियों की हत्या कर दी गई।
1981 चीन ने कैलाश और मानसरोवर के लिये सड़क मार्ग खोला।
1989 सर्बिया के राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोएविच ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने सेर्बिया के राष्ट्रीय विकास के भविष्य में सशस्त्र लड़ाई की संभावना का वर्णन किया।
2004 इराक़ी अंतरिम सरकार को इराक का शासन सौंपने के बाद गठबंधन अनंतिम प्राधिकरण भंग हो गया।
2005 अफगानिस्तान में युद्ध-तीन अमेरिकी नौसेना नौसेना सील और 16 अमेरिकी विशेष अभियान बलों के सैनिकों को अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में एक विफल जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया।

ओवैसी को सांसद रहने का नैतिक अधिकार नहीं

गिरीश पंकज

इस देश में धीरे-धीरे देश-विरोधी मानसिकता वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं । %भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह% का नारा हो,चाहे भारत माता को डायन कहना; लोग पूरी बेशर्मी के साथ ऐसी बातें कह देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती । दिखावे के लिए तात्कालिक कार्रवाई तो होती है लेकिन लंबे समय के बाद उसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आता। मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया जाता है। अभी हाल ही में 18 वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद सदन में शपथ ग्रहण करने के बाद एआइएमआइएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अंत में जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। नि:सन्देह यह देशविरोधी हरकत थी। उनके इस नारे का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया जाना चाहिए ,और कायदे से संविधान के अनुच्छेद 102 (4) के तहत मामला पंजीबद्ध करके इनकी सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए। इस अनुच्छेद में साफ-साफ लिखा है कि कोई भी सांसद किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा जताएगा तो उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है । और ओवैसी ने स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन का नाम लिया। उन्होंने हिंदुस्तान की जय या भारत माता की जय नहीं कहा। (ऐसा तो खैर वह कभी कह भी नहीं सकते) पूरी दुनिया को पता है कि फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने किस तरह से इज़राइल के लोगों को तबाह करने की हिमाकत की । इज़राइल ने भी जवाबी हमले कि और फिलिस्तीन को उसने भी नुकसान पहुंचाया। दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं । यह उनका अपना मामला है । लेकिन भारत का कोई सांसद लोकसभा में शपथ लेते हुए फिलिस्तीन की जय का नारा लगाए, तो इससे समझ में आता है कि उसका अपना एजेंडा क्या है । इसी आधार पर कायदे से ओवैसी की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए ।

राष्ट्रपति महोदया को ओवैसी पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां दिक्कत यही है कि हम लोग किसी भी मामले को टाल देते हैं। जबकि टाला नहीं चाहिए। खास कर जब बात देश की गरिमा की हो। भारत देश के संसद के भीतर ओवैसी में भारत माता की जय नहीं कहा, हिंदुस्तान की जय नहीं कहा, उसने फिलिस्तीन की जय कहा। यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। इसे हल्के में कदापि नहीं लेना चाहिए। संतोष की बात है कि प्रतिरोध करने वाले कुछ लोग हमारे यहां मौजूद हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मांग की है कि देशविरोधी हरकत करने वाले ओवैसी पर कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द करें । हालाँकि यह भी हो सकता है कि आजकल में ओवैसी अपने इस कृत्य के लिए माफी भी मांग ले लेकिन मुझे लगता है उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। और कम-से-कम एक-दो वर्ष के लिए उनकी सदस्यता को निलंबित किया जाना चाहिए ताकि उनको सबक मिले और दूसरे भी सावधान हो जाएँ कि भारत की संसद के भीतर भारत माता या भारत/हिंदुस्तान की जय ही का ही

नारा लगाया जा सकता है । ठीक है कि एक सांसद ने हिंदू राष्ट्र की जय कहा। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि भारत अभी संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है । लेकिन इस नारे के पीछे देश विरोधी मानसिकता नहीं है। वह अपने सनातन धर्म के प्रति अतिरिक्त लगाव के कारण वैसा कह गए, जो नहीं कहा जाना चाहिए था। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर भी उनकी गलती क्षम्य है क्योंकि इस देश का एक नाम हिंदुस्तान भी है। लेकिन ओवैसी की गलती अक्षम्य है। यह साफ है कि हिंदू राष्ट्र की जय के नारे से चिढ़ कर ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय का नारा लगाए । उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया इसलिए उनकी हरकत देश विरोधी कही जाएगी। और कायदे से उन पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और उन्हें फौरन सांसद पद के अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद जब कुछ लोगों ने ओवैसी से प्रश्न किया कि आपने ऐसा क्यों कहा तो मसीहाई अंदाज में कहने लगे कि वह हाशिये पर पड़े लोगों के मामले उठाते रहेंगे । हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि फिलिस्तीनी लोग हाशिये पर पड़े हैं। उनकी क्रूर हरकतें पूरी दुनिया ने देखी हैं।हाशिये के लोग इतने बर्बर नहीं होते। तरह खून खराबा नहीं करते। तो हाशिये की बात तो बेमानी है। हाशिये के लोगों की आवाज आपको उठानी है तो उन देशों के लोगों की आवाज उठा सकते थे,जहां के बच्चे भुखमरी के शिकार हैं। पीओके और पाक के बलूचियों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सकते थे । आपने ईरान की महिलाओं का मामला नहीं उठाया, जो बुर्के के विरुद्ध संघर्ष कर रही हैं और इस कारण उन पर अत्याचार भी हो रहे हैं ।वे औरतें हाशिये की औरतें हैं। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को हाशिये में पड़े लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

बहरहाल, अगर समय रहते ओवैसी पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है कल को भावावेश में आकर कोई मुस्लिम सांसद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दे । इस देश में कुछ भी संभव है। समय-समय पर हम इन खबरों से दो-चार होते ही रहते हैं कि जुलूस में कोई पाकिस्तान के झंडे दिखा रहा है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इस देश में एक अजीब किस्म का लोकतंत्र है। यहां सबको अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग देशविरोधी आचरण करने लगें। देश के खिलाफ नारे लगाने लगे! विदेशी देश का झंडा लहराने लगे!! लेकिन यह सारी विसंगति इस देश में दिखाई देती है। और संसद में ओवैसी ने जो हरकत की वह तो विसंगति की पराकाष्ठा ही कही जाएगी। कायदे से तो उन्हें सदन में बने रहने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। उन्हें तो फिलिस्तीन की नागरिकता ग्रहण कर लेनी चाहिए।

उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति महोदया ओवैसी के बयान को गंभीरता से लेंगी और अनुच्छेद 102 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं ,उसके तहत ओवैसी की सदस्यता समाप्त करने पर विचार करेंगी। अगर ओवैसी अपने कुकृत्य के लिए माफी मांग लेते हैं, तो भी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तो जरूर की जानी चाहिए और कुछ समय के लिए ही सही, उनकी सदस्यता निलंबित की जानी चाहिए। ताकि दोबारा कोई भी सदन में ऐसी हरकत न कर सके । सदन में ही क्यों, बाहर भी किसी भी देश के समर्थन में नारे नहीं लगने चाहिए। नारे लगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय के ही लगने चाहिए।

क्या सुनक को मिलेंगे भारतवंशियों के वोट?

विवेक शुक्ला

क्या ब्रिटेन में आगामी 4 जुलाई को होने वाले आम चुनावों के बाद भी देश के पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने पद पर बने रहेंगे? क्या ऋषि सुनक की कंजरवेटिव पार्टी को ब्रिटेन में बसे हिंदू वोट देंगे? क्या भारतवंशियों के वोट लेबर पार्टी को भी मिलेंगे? बेशक ये सवाल महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटेन की 2011 की जनगणना के अनुसार, वहां भारतीय मूल के लगभग 15 लाख लोग हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 2 ।5 प्रतिशत है। ब्रिटेन में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। ये बाकी प्रवासी समूहों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी तरह से शिक्षित है। ब्रिटेन में भारतीय सबसे मालदार लोग माने जाते हैं। हिंदुजा, लक्ष्मी मित्तल, स्वराज पाल जैसे भारतवंशी ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों की सूची में जगह पाते हैं। संडे टाइम्स की बीती मई में जारी ब्रिटेन के सबसे बड़े धनकुबेरों की सूची में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का 245 वां स्थान है। अक्षता इंफोसिस टेक्नोलॉजीज के फाउंडर चेयरमैन एन।आर। नारायणमूर्ति की पुत्री हैं। दरअसल ब्रिटेन में बसे भारतीयों का लंबे समय तक झुकाव लेबर पार्टी के साथ रहा है। लेबर पार्टी की सरकार के दौर में ही भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति मिली थी। हालांकि हालिया सर्वेक्षणों से पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि भारतीयों का लेबर पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी, दक्षिणपंथी कंजरवेटिव पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ा है। लंदन में 1970 के दशक से बसे हुए लेखक विनोद चव्हाण मानते हैं कि आगामी आम चुनावों में ब्रिटेन में बसे हिंदू वोटर कंजरवेटिव पार्टी के हक में एकमुश्त वोट दे सकते हैं। ये खबर ऋषि सुनक और उनकी कंजरवेटिव पार्टी को सुकून दे सकती है। एक बात समझनी होगी कि जब हम ब्रिटेन में बसे भारतीयों की बात करते हैं, तब उनमें वे भी शामिल होते हैं जो ब्रिटेन में ईस्ट अफ्रीका, कैरीबियाई टापू देशों और अन्य स्थानों से आकर बसते रहे हैं। ऋषि सुनक का परिवार 1960 के दशक में केन्या से ब्रिटेन में जाकर बसा था। हालांकि उनके पुरखे मूल रूप से पंजाब से थे। एक राय यह भी है कि नरेंद्र मोदी के 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटेन में बसे बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कंजरवेटिव पार्टी के समर्थक हो गए। इनमें हिंदू सर्वाधिक हैं। वहां भारतवंशियों की कुल आबादी में हिंदू दस लाख से अधिक हैं। ब्रिटेन के हिंदुओं का 2010 से रुख कंजरवेटिव पार्टी की तरफ होने लगा था। उन भारतीयों में दूसरी और तीसरी पीढ़ी के धनी और शिक्षित हिंदू भी थे। पिछले 20-25 वर्षों में भारत से एक नया प्रवासी समुदाय ब्रिटेन पहुंचा है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी पेशेवर वगैरह हैं। ये सब अपने को कंजरवेटिव पार्टी का वोटर बताते हैं। यूं ही भारतवंशियों का लेबर पार्टी से मोहभंग नहीं हुआ। हुआ यह कि लेबर पार्टी ने 2019 में एक प्रस्ताव पारित करके जम्मू-कश्मीर के लोगों को 'आत्मनिर्णय का अधिकार' देने की मांग की। लेबर पार्टी के इस प्रस्ताव के कारण ब्रिटेन में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा लेबर पार्टी से दूर होने लगा। उसे लगा कि यह भारत के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। इस बीच, ऋषि सुनक करीब दो साल पहले 2022 में ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने। इसके चलते वहां के हिंदुओं और कंजरवेटिव पार्टी के बीच संबंध और गहरे हो गए।

एआई कमजोर लोकतंत्रों को बेहतर बना सकता है

जसप्रीत बिंद्रा

पिछले दो वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी की कहानी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इससे उत्पन्न उत्साह एवं व्यवधान का बोलबाला रहा है। हालांकि वर्ष 2023 के उत्तरार्ध में कॉपीराइट, पूर्वाग्रह, निजता और डीपफेक जैसे नैतिक मुद्दों के सामने आने से इस कहानी में थोड़ी कड़वाहट घुलने लगी। दुनिया के अधिकांश लोकतंत्रों में या तो चुनाव हो चुके हैं या होने वाले हैं, इसलिए 2024 में एआई की पहली प्रमुख नैतिक परीक्षा होगी कि वह लोकतंत्र की मदद करेगा या उसे नष्ट कर देगा।

भारत में तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया और अन्य प्रमुख लोकतंत्रों में इस साल महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। हालांकि डीपफेक जेनरेटिव एआई से पहले से ही अस्तित्व में है, लेकिन सोरा और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे उत्पादों ने उसके उत्पादन को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे अब बड़े पैमाने पर इसे बनाना आसान, तेज और सस्ता हो गया है। सोशल मीडिया पर भी हम सब शीर्ष पर हैं, जहां व्हाट्सएप, टिकटॉक और इसी तरह के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वैश्विक स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं।

इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश और स्लोवाकिया में चुनाव हुए, जिसमें डीपफेक भी एक पक्ष बन गया। बांग्लादेश के एक विपक्षी नेता को फलस्तीन के समर्थन के मुद्दे पर दुविधा की स्थिति में दिखाया गया, इस तरह का रुख अपनाना उस देश में विनाशकारी है। स्लोवाकिया के चुनाव में भी एक प्रमुख दावेदार ने कथित तौर पर चुनावों में धांधली की बात कही थी और इससे?भी चिंताजनक बात थी कि उन्होंने बीयर की कीमत बढ़ाने की बात की, जो कथित तौर पर उनकी हार का कारण बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की नकली आवाज में लोगों से यह अपील की गई कि वे अमेरिकी प्राइमरी में मतदान नहीं

करें। वर्ष 2016 के कैंब्रिज एनालिटिका विवाद की यादें अब भी ताजा हैं। बड़े चुनावों के नजदीक आते ही खतरे की घंटी बज गई है।

यहीं पर मैं इसके एक दूसरे पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा। जरा पाकिस्तान को देखिए, वहां भी इसी वर्ष की शुरुआत में चुनाव हुए। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में थे। उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न छीन लिया गया और उनके कुछ उम्मीदवारों को धमकाया गया और कुछ को जेल में भी डाल दिया गया। हालांकि अंतत: दूसरी पार्टियों की जीत की घोषणा की गई, लेकिन ज्यादातर खबरें दावा करती हैं कि भारी धांधली और हेराफेरी के बावजूद इमरान खान की पार्टी ने अच्छी सफलता पाई। खान ने जेल में रहते हुए पूरे देश में चुनाव प्रचार करने के लिए जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया और इस कहानी को पलट दिया कि एआई लोकतंत्रों को नष्ट करती है। जेनरेटिव?एआई का इस्तेमाल करके उन्होंने मतदाताओं से अपनी पार्टी के लिए मतदान करने का आग्रह करते हुए फुटेज तैयार किया और इसे यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन चैनलों पर खूब शेयर किया गया। लोगों ने उनके आह्वान पर ध्यान दिया और रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया, जिससे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में सफलता मिली। पाकिस्तान ने दिखा दिया कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को नष्ट करने के बजाय उसे मजबूती दी जा सकती है। यहां मैं डीपफेक की विनाशकारी शक्ति से इन्कार नहीं कर रहा हूं, और मुझे डर है कि भारत के किसी भी चुनाव और अन्य चुनावों में इसका इस्तेमाल विमर्श को भड़काने और मनगढ़ंत कथानक को आकार देने के लिए किया जा सकता है। हालांकि चुनावों, जो लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है, को बेहतर बनाने के लिए एआई बहुत कुछ कर सकता है। पाकिस्तान का उदाहरण इसका रचनात्मक तरीका है। चुनावों में पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता बढ़ाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी उन्नत डाटा विश्लेषण क्षमताएं वास्तविक समय में चुनाव से संबंधित डाटा की निगरानी कर सकती हैं, जिससे धोखाधड़ी का संकेत देने वाली किसी भी अनियमितता की पहचान की जा सकती है। एआई एल्गोरिदम मतदाता पंजीकरण या मतदान में अनियमितताओं के पैटर्न का पता लगा सकते हैं। एआई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की सुरक्षा में भी सुधार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, खतरे का पता लगाने वाले एल्गोरिदम संभावित साइबर खतरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

जेनरेटिव एआई स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके स्थानीय बोली में उम्मीदवारों और उनके घोषणापत्रों पर बेहद व्यक्तिगत सामग्री तैयार करते हुए मतदाताओं की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण राजनीतिक जागरूकता बढ़ा सकता है और विशेष रूप से हाशिये पर पड़े समूहों के लोगों को सोच-समझकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जेनरेटिव एआई इस काम को बड़े पैमाने पर, बहुत कम लागत में, उच्च दक्षता के साथ करने में मदद कर सकता है, जिससे कम पैसे वाले उम्मीदवार भी सशक्त बन सकेंगे। एआई द्वारा संचालित प्रणालियां दिव्यांग मतदाताओं की पहुंच को भी बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, एआई द्वारा संचालित ध्वनि पहचान प्रणालियां दृष्टि बाधित मतदाताओं को मतदान करने में सहायता कर सकती हैं।

भाजपा को उत्तर प्रदेश में पराजय के बोध से उबरना ही होगा

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 लोकसभा चुनावों में हैरान करने वाले चुनाव परिणाम दिये हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का नारा दिया था किंतु भाजपा गठबंधन मात्र 37 सीटों पर ही सिमटकर रह गया। भाजपा अयोध्या वाले संसदीय क्षेत्र फैजाबाद तक से हार गई जहाँ प्रभु श्रीराम दिव्य भव्य एव नव्य राम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं तथा विविध प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं । ये हार हर किसी को आश्चर्य में डाल रही है। आज भी हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि अरे भाजपा फैजाबाद में कैसे हार गई ? आखिर क्यों, फिर यह चर्चा लंबी खिंच जाती है और भाजपा समर्थकों व शुभचिंतकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगती हैं कि अब होगा क्या? भाजपा का हर शुभचिंतक अपने अपने स्तर पर गहन समीक्षा कर रहा है किंतु क्या बीजेपी आलाकमान व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनमानस की चिंताओं के साथ खड़े हैं या नहीं। महिलाएं भी अयोध्या पराजय पर चर्चा कर रही हैं कि फ्री राशन, घर, शौचालय, दवाई व राम मंदिर के बाद भी भाजपा क्यों पराजित हो गई?

प्रदेश में भाजपा की पराजय के जो मुख्य बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें प्रत्याशियों का गलत चयन, राजग गठबंधन के नेताओं की गलत बयानबाजी, क्षत्रियों व राजपूतों की नाराजगी को हलके में ले लेना तथा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोट जिहाद का हो जाना आदि तो था ही मीडिया की मानें तो संघ व भाजपा के बीच आतंरिक टकराव भी एक कारण रहा। वर्तमान समय में जब नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में ऐसे ऐसे अदभुत कार्य हो रहे हैं जिनका प्रभाव हजार साल तक रहने वाला है उस समय संघ नेतृत्व ने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? क्या वो सच ही मोदी जी का अहंकार तोड़ना चाहते थे या अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे थे? क्या स्वयं को मातृ संस्था कहने वालों को भी आत्मसंयम का परिचय नहीं देना चाहिए था? ये कठिन प्रश्न मीडिया और सोशल मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल चुके हैं। इसे पूरे दावानल में आम सनातनी ठगा सा खड़ा है।

प्रदेश में भाजपा की पराजय के साइड इफैक्ट हर तरफ दिखने लगे हैं। जिन जिलों में इंडी गठबंधन के सांसद बने हैं उन जिलों में आपराधिक गतिविधियों में जबरदस्त तेजी आई है। सीतापुर जिले में नए बने कांग्रेस सांसद ने थाने में धरना देकर एक नाबालिग अपराधी को थाने से ही छुड़ा लिया। इकरा हसन के समर्थकों ने हिन्दुओं पर हमला

बोला और सोनभद्र में एक हिन्दू परिवार घर छोड़ने को विवश है, ऐसी ही अनेक घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यव्यहार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में वाहन जांच के नाम पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ अभद्रता की गई यद्यपि घटना के बाद ट्रैफिक दारोगा आशुतोष त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। राकेश त्रिपाठी का कहना है कि पुलिस भाजपा का झंडा लगा देखकर वाहन को रोक रही है जब लखनऊ में भाजपा प्रवक्ता के साथ इस प्रकार की घटना घटित हो रही है तब प्रदेश के दूसरे जिलों में क्या हाल हो रहा होगा। प्रदेश का पुलिस प्रशासन अभी भी लापरवाही तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त है तथा महिला थाने तक में पीड़ितों से रिश्वत मांगी जा रही है। हालाँकि अकबरनगर का अतिक्रमण हटाकर सरकार ने सख्त प्रशासन की अपनी छवि बचाने का प्रयास किया है।

मीडिया की मानें तो राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने उप्र के अवध क्षेत्र की सीटों पर जीतने का जोर नहीं लगाया, अगर यहाँ पर ताकत लगा दी जाती तो भाजपा की कम से कम आठ सीटें तो और बढ़ ही जातीं किंतु मेड़ ही खेत से मुँह मोड़ चुकी हो तो क्या ही कहा जाए। आम सनातनी योगी मोदी की कम सीटों से दुखी है और समाचारों में देखता है कि ये संघ के असहयोग के कारण हुआ है तो उसका मन व्यथित होता है और संघ पर दशकों से किया गया विश्वास डगमगा जाता है। अहंकार किसी का भी हो लेकिन केवल योगी या मोदी नहीं, संघ भी हारा है और अस्तित्व की लड़ाई से जूझ रहा हिन्दू भी।

लोकसभा चुनावों के मध्य भाजपा व संघ के बीच मनमुटाव के समाचारों, गलत प्रत्याशी के चयन और उससे भी आगे बढ़कर चयनित प्रत्याशी की गलतबयानी के कारण एक सबसे महत्वपूर्ण सीट हाथ से निकल गई, जिसका व्यापक नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। रामभक्त विपक्ष के निशाने पर हैं, उनपर तंज कसे जा रहे हैं। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर व अयोध्या के विकास कार्यों पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, विपक्ष उसको हवा दे रहा है। अभी हल्की बारिश में अयोध्या धाम के पुराने रेलवे स्टेशन की बाउंड्रीवाल गिर गई जिसको नए स्टेशन की बताकर विकास कार्यों पर कीचड़ उछाला गया। भला हो समय रहते जागरुक नागरिकों ने उसका खंडन कर दिया।

उप्र में योगी ओर केंद्र में मोदी जी कमजोर हो गये तो नुकसान तो हिंदुत्व का ही होना है। संघ अगर अभी नहीं चेता तो उप्र में भी वहीं हालात हो जाएंगे जो केरल से लेकर तमिलनाडु और बंगाल तक हो रहा हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में भाजपा और संघ के कार्यकताओं की हत्याएं हो रही हैं। संघ को अपनी शाखा तक लगाने तक में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू जनमानस अपने उत्सव तक नहीं मना पा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपील करी थी कि जरा सी गलती से सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और 2024 में कुछ लोगों के संकुचित सोच के कारण वही गलती हो गई है।

उत्तर प्रदेश में भी जब सपा, बसपा व कांग्रेस आदि दलों की सरकारें हुआ करती थीं तो संघ के स्वयंसेवक जब अपनी शाखा लगाने के लिए पार्कों में जाते थे तब सपा और बसपा के गुंडे व समर्थक भगवा ध्वज उठाकर बहा देते थे और स्वयंसेवकों के साथ दुर्व्यव्यहार किया जाता था। योगी राज मे कम से कम संघ की शाखाएँ सुरक्षित हैं। प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गांवों में हिन्दू जनमानस अपने घरों में सुंदर कांड व रामचरित मानस का पाठ नहीं करा पाता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को योगीराज में हो रहे हिन्दू हित के कार्यों पर भी अपनी दृष्टि डालनी चाहिए थी। लगता है कि योगी सरकार के अच्छे कार्य को संघ व संगठन की दृष्टि से नजरअंदाज कर दिया गया। संघ को विचार करना चाहिए कि 2017 के पूर्व प्रदेश के क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? अगर भाजपा और संघ के बीच मनमुटाव को तत्काल कम नहीं किया गया तो प्रदेश में रामराज्य की संकल्पना ध्वस्त हो जाएगी। वर्तमान लोकसभा चुनावों में भाजपा की पराजय का एक बहुत बड़ा कारण प्रशासनिक अधिकारी व सरकारी कर्मचारी भी रहे जो योगी जी से केवल इसलिए छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि इस सरकार में उन्हें काम करना पड़ता है। इनमें से कुछ खुले आम पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की आड़ में विरोधी दलों के साथ मिल गये और प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम करवाने के लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ी। अनेक जगहों से समाचार प्राप्त हो रहे है कि कुछ अधिकारी खुलेआम बीजेपी को हराने के लिए ही काम कर रहे थे।

कहानी फॉदर ऑफ लोकसभा की

अभिनय आकाश

जीवन में नाटकीयता अक्सर अप्रत्याशित होती है। अभी एक-दो दिन पहले की ही बात है। चर्चा चल रही थी कि क्या सबसे कद्दावर नेताओं में से एक भाजपा के लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह लोकसभा के नए अध्यक्ष होंगे। लेकिन 9 जून के शपथ ग्रहण के बाद इन कयासों पर विराम लग गया। फिर बात चली कि जो भी नया होगा वो आंध्र प्रदेश से होगा क्योंकि टीडीपी का समर्थन भी जरूरी है, कई नाम भी सामने आने लगे। लेकिन अटकलों पर भी विराम चिन्ह लग गया। अब लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी ने कोटा से सांसद और पिछली लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया तो विपक्ष ने के सुरेश को उम्मीदवार के तौर पर उतारा। पहले माना जा रहा था कि विपक्ष इस पर वोटिंग कराने की मांग करेगा। लेकिन विपक्ष ने ऐसी कोई मांग नहीं की और ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास कर दिया गया। ओम बिरला के आसन तक पहुंचने पर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने कहा कि आपकी चेयर है, आप संभालें। ये तो हो गई नए लोकसभा के स्पीकर की बात। मगर आज हम बात उस लोकसभा स्पीकर की करेंगे जिन्हें फॉदर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभी की कुर्सी पर अभी तक 18 स्पीकर विराजमान हो चुके हैं। अब लोकसभा को 19वां स्पीकर ओम बिरला के रूप में मिल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर सबसे पहले बैठने वाले अध्यक्ष कौन थे। उनका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है और उन्हें फॉदर ऑफ लोकसभा व दादा साहेब जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। प्यार से लोग उन्हें दादा साहेब ही बुलाया करते थे। लेकिन फॉदर ऑफ लोकसभा का खिताब मिलने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के बाद गणेश मावलंकर ने कुछ ऐसा कहा जो प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के दिल को छू गया। जब उन्हें लोकसभा ने चुना तो संसद के 394 सदस्यों का समर्थन मिलने की संतुष्टि से वो चमक उठे। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास था लेकिन वो इतने भावुक हो गए कि स्पीकर की कुर्सी पर खड़े हो गए। उन्होंने जोरदार भाषण दिया और अंत में कहा कि एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी से कार्य करने का भाव ही हमें नतीजे देगा। नेहरू ने मावलंकर का ये भाषण सुनकर उन्हें फॉदर ऑफ लोकसभा की उपाधि दी। जीवी मावलंकर आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। लेकिन उनके विचार आज भी लोगों के जेहन में जिंदा हैं। देश के इतिहास में स्पीकर के पद को लेकर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुआ था। उस समय कांग्रेस की ओर से जवाहर लाल नेहरू ने जीवी मावलंकर का नाम स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर आगे रखा। वहीं एसके गोपालन ने शंकर शांताराम मोरे का नाम स्पीकर के पद के उम्मीदावरा के तौर पर प्रस्तावित किया। बाद में वोटिंग की नौबत आई। मावलंकर के समर्थन में 394 वोट पड़े जबकि विरोध में 55 वोट गए। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात ये रही कि शांता राम मोरे ने भी मावलंकर के पक्ष में वोट किया। उन्होंने कहा कि ये संसद की परंपरा के अनुरूप होगा कि दो उम्मीदवार जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं वो एक दूसरे को ही वोट कर रहे हैं। मावलंकर अपनी निष्पक्षता के लिए बड़े मशहूर थे। कांग्रेस के सदस्य होने के बाद भी उन्हें किसी भी पार्टी के सदस्य के तौर पर नहीं देखा जाता था। जीवी मावलंकर एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सबकुछ न्यौछावर कर दिया। भारत को आजादी मिलने के बाद संविधान 1950 में लागू हुआ। पहले लोकसभा चुनाव के बाद 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती स्पीकर के चुनाव की थी। लोकसभा के संचालन में अध्यक्ष का काम बहुत ही जिम्मेदारियों से भरा और संवेदनशील होता है। इस पद को संभालने के लिए जीवी मावलंकर से बेहतर कोई और नहीं हो सकता था। इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। जीवी मावलंकर के खिलाफ साल 954 में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। लेकिन लोकसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया था। मावलंकर अक्सर ही प्रधानमंत्री के साथ असहमत होते थे। उदाहपण के तौर पर अध्यादेश के मुद्दे पर नेहरू और मावलंकर के विचार बिल्कुल अलग अलग थे। मावलंकर ने कहा था कि ये काम करने का लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सरकार अध्यादेश ला सकती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसएल शकधर ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि मावलंकर ने नेहरू को दूसरा बयान देने से रोक दिया था। क्योंकि ये लोकसभा के नियमों का उल्लंघन था। नेहरू ने उनके फैसले के सामने शालीनता से सिर झुकाया।

दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क

भारत का पूर्वोत्तर राज्य अपनी अनूठी प्राकृतिक सुन्दरता को समेटे हुए है और यही वजह है कि पूर्वोत्तर राज्य लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करता है। भारत के इस हिस्से में एक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस तैरते हुए पार्क की बात कर रहे है।

भारत का पूर्वोत्तर राज्य अपनी अनूठी प्राकृतिक सुन्दरता को समेटे हुए है और यही वजह है कि पूर्वोत्तर राज्य लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करता है। भारत के इस हिस्से में एक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस तैरते हुए पार्क की बात कर रहे है ? तो दोस्तों, हम बात कर रहे है भारत के मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की। इस झील का नाम है लोकतक झील और इस झील की खासियत है कि यहां दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो पानी में तैरता है। इस पार्क को कीबुल लामजो के नाम से जाना जाता है और इस पार्क की खूबसूरती देखने लायक है। जिसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते है इस पार्क से जुड़ी खासियत के बारे में-

लोकतक झील की खासियत -

इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिशनुपुर जिले में ये लोकतक झील स्थित है। दुनिया में यह झील तैरती हुई झील के नाम से भी मशहूर है। इस झील में बने हुए प्राकृतिक द्वीप बहुत-ही सुन्दर और देखने लायक हैं और इनको फुमदी कहा जाता है। इन द्वीपों में मौजूद सबसे बड़ा द्वीप 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इन फुमदियों पर स्थानीय मछुआरे रहते हैं 7 इसके साथ ही प्रकृति के सुंदर नजारों पर तैरती यह लोकतक झील मणिपुर को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनाती है।

झील पर तैरता है ये पार्क

दुनियाभर में यह झील पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है और इस आकर्षण का कारण है पार्क का झील के ऊपर तैरना और इसी वजह से इस अनोखे पार्क को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते है। इस पार्क को विश्व से विलुप्त होते संगाई हिरनों का आखिरी और प्राकृतिक घर भी कहा जाता है। संगाई हिरन मणिपुर का राज्य पशु भी है।

पार्क में मौजूद है ढेरों वनस्पति और पशु-पक्षी

इस पार्क में आपको एक-से-एक पशु-पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। जिसमें ब्लैक ड्रोंगोस, जंगल क्रो, येलो हेडेड वैगेटल, जंगली सूअर, ब्रो एंटेलियर, कोबरा और पायथन के अलावा 1000 से भी अधिक पशु-पक्षी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस पार्क में लगभग 450 से भी ज्यादा किस्मों के ऑर्किड पर 100 से अधिक जलीय वनस्पतियां पायी जाती हैं।

यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन-सा है ?

इस पार्क को देखने के बाद आप आसपास की और भी खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं जैसे-कंगला फोर्ट, शहीद मीनार, मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन। इस जगह आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच का है। यहां पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच कभी भी घूमने जा सकते हैं।

कैसे पहुंचे ?

हवाई मार्ग द्वारा- यदि आप हवाई मार्ग के द्वारा जाना चाहते है तो मणिपुर की राजधानी इंफाल, इस पार्क से 53 किमी की दूरी पर है जो दिल्ली (2,503 किमी), गुवाहाटी (469 किमी) और कोलकाता (1,620 किमी) जैसे प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

रेलमार्ग से - यदि आप रेल से जाना चाहते है तो दीमापुर सबसे पास का रेलवे स्टेशन है, जो कि इम्फाल से 215 किमी की दूरी पर है। सड़क मार्ग द्वारा- इंफाल नेशनल हाइवे 39 के माध्यम से गुवाहाटी (469 किमी) और राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के माध्यम से सिलचर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इम्फाल बस या प्राइवेट वाहनों के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है।

● रौनक

अफ्रीका जा रहे हैं घूमने तो वहां पर यूनोस्को की विश्व धरोहर स्थलों को जरूर देखें

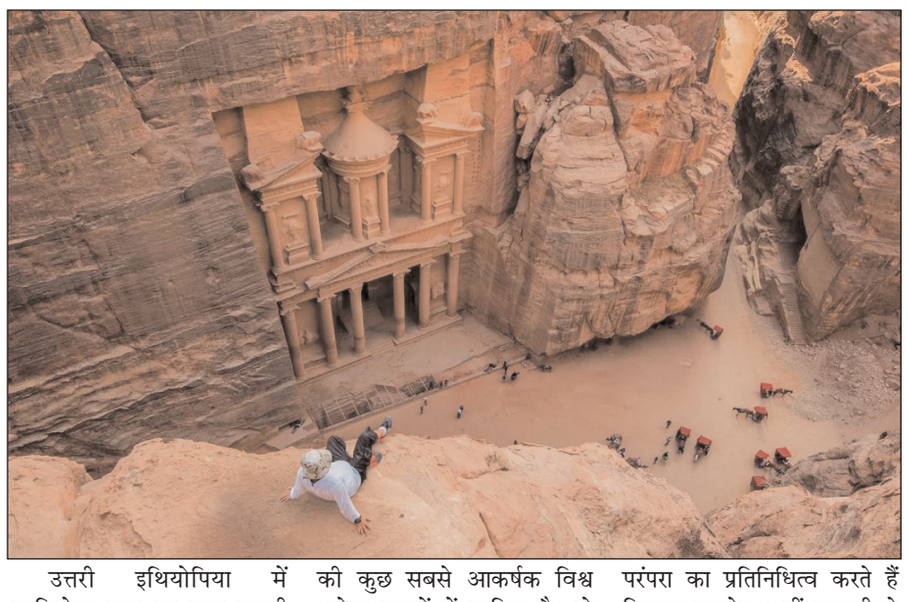

उत्तरी इथियोपिया में लालिबेला शहर का सुदूर पहाड़ी गाँव 11 शानदार मध्ययुगीन चर्चों का घर है और इन्हें एक ही चट्टान से बनाया गया है। इन रहस्यवादी कृतियों ने इस पर्वतीय शहर को उपासकों और आगंतुकों के लिए गौरव और तीर्थ के रूप में बदल दिया है।

पूरे विश्व में, यूनेस्को के सैकड़ों विश्व धरोहर स्थल हैं। ये हमारे समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा गया हैं। अकेले अफ्रीका में ही 89 विरासत स्थल हैं जो दुनिया की कुछ सबसे आकर्षक विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। तो चलिए आज हम आपको अफ्रीका की कुछ बेहतरीन यूनोस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में शायद अब तक भी आपको जानकारी ना हो- उत्तरी इथियोपिया में लालिबेला शहर का सुदूर पहाड़ी गाँव 11 शानदार मध्ययुगीन चर्चों का घर है और इन्हें एक ही चट्टान से बनाया गया है। इन रहस्यवादी कृतियों ने इस पर्वतीय शहर को उपासकों और आगंतुकों के लिए गौरव और तीर्थ के रूप में बदल दिया है। ये चर्च एक निर्माण परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका उपयोग 6 वीं शताब्दी से इथियोपिया में किया जाता रहा है। इन विशेष चर्चों का श्रेय राजा लालिबेला को दिया जाता है, जिन्होंने 13 वीं शताब्दी में शासन किया था। यहां जाने का सबसे अच्छा समय टिम्मेट के दौरान है। यह जनवरी में मनाया जाने वाला एक बेहद खास त्यौहार है। माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे ऊँचा स्थान है, जो आसपास के मैदानों के ऊपर बर्फीली चोटी के साथ खड़ा है।

पहाड़ जंगलों से घिरा हुआ है, और महाद्वीप पर पाए जाने वाले कुछ सबसे अद्भुत जानवर हैं। किलिमंजारो के पर्वतारोहियों को आस-पास के सवाना और आकर्षक ग्लेशियरों और प्रभावशाली बर्फ की चट्टानों के विस्मयकारी नजारें देखने का मौका मिलता है।

प्राचीन थेब्स, मिस्र

यदि आप मिस्र के कुछ वास्तविक इतिहास को देखना चाहते हैं, तो बस लक्सर शहर से दक्षिण की ओर जाएं। यहां पर आपको यूनेस्को साइट प्राचीन थेब्स को देखने का मौका मिलेगा। लक्सर कभी प्राचीन मिस्र की राजधानी थी, लेकिन आज इसे दुनिया के सबसे बड़े ओपन-एयर संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। लक्सर और सेटी के राजसी मंदिर परिसरों में शानदार सूर्यास्त का दृश्य होता है। खंडहरों का दौरा करने के बाद, शाम को आप कर्णक मंदिर के साउंड शो में भाग जरूर लें।

एक बार एक प्राचीन व्यापारिक साम्राज्य की राजधानी, ग्रेट ज़िम्बाब्वे दक्षिण-पूर्वी पहाड़ियों में पाया जाता है जो अब ज़िम्बाब्वे का देश है। भले ही ये खंडहर अफ्रीका में अन्य यूनेस्को साइटों के रूप में आश्चर्यजनक नहीं हैं, लेकिन वे मान्यता के योग्य हैं।

सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया

कुंभलगढ़ किले को सात विशाल द्वारों से बनाया गया है। इस भव्य गढ़ के अंदर मुख्य भवन बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और मम्मादेव मंदिर हैं। कुम्भलगढ़ किला परिसर में लगभग 360 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं, और बाकी हिंदू हैं। कुंभलगढ़ किले को सात विशाल द्वारों से बनाया गया है। इस भव्य गढ़ के अंदर मुख्य भवन बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और मम्मादेव मंदिर हैं। कुम्भलगढ़ किला परिसर में लगभग 360 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं, और बाकी हिंदू हैं।

राजस्थान का अपना एक अलग समृद्ध इतिहास है, जो इसे सैलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाता है। यहां के किले व महल अनजाने ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे तो जयपुर के आमेर फोर्ट से लेकर जैसलमेर के किले लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन्हीं के बीच कुंभलगढ़ का किला अपना एक अलग महत्व रखता है। कुम्भलगढ़ किला पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर मेवाड़ का किला है। इस किले की खासियत है उसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार। यह राजस्थान के हिल फॉर्ट्स में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है। 15 वीं शताब्दी के दौरान राणा कुंभा द्वारा निर्मित इस किले की दीवार को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार का दर्जा प्राप्त है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन कुंभलगढ़ को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 80 किलोमीटर उत्तर में उदयपुर के जंगल में स्थित, कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। किले की दीवार 36 किलोमीटर की विशाल लंबाई तक फैली हुई है और इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अरावली रेंज में फैला कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्मस्थान है। यही कारण है कि राजपूतों के दिलों में इस किले के प्रति एक विशेष स्थान है। 2013 में, किले को विश्व धरोहर समिति के 37 वें सत्र में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।

किले को सात विशाल द्वारों से बनाया गया है। इस भव्य गढ़ के अंदर मुख्य भवन बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और मम्मादेव मंदिर हैं। कुम्भलगढ़ किला परिसर में लगभग 360 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं, और बाकी हिंदू हैं। इस किले की एक खासियत यह भी है कि इस भव्य किले को वास्तव में युद्ध में कभी नहीं जीता गया था। हालांकि इस पर केवल एक बार मुगल सेना द्वारा छल द्वारा कब्जा कर लिया गया था जब उन्होंने किले की पानी की आपूर्ति में जहर डाल दिया था।

मिताली जैन

बिना तेल और घी के जलता है दीया, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े चमत्कारी रहस्य

भारत में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। यह मंदिर है भगवान तिरुपति बालाजी का जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मन्दिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है।

भारत में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। यह मंदिर है भगवान तिरुपति बालाजी का जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मन्दिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वैंकटेश्वर बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित है और तिरुपति के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ दर्शन कर ले उसके भाग खुल जाते हैं। इस मंदिर की लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ है पर क्या आप मंदिर के चमत्कारी रहस्यों के बारे में जानते हैं। आज हम आपको इन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं-

मान्यता है कि जब भगवान की पूजा की जाती है तो उनकी मूर्ति मुस्कुराने लगती है। भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति में माता लक्ष्मी भी समाहित है। मान्यता है कि भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर की मूर्ति इस मंदिर में स्वयं प्रकट हुई थी।

कहा जाता है भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति पर लगे हैं बाल असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। जब आप मंदिर के गर्भ गृह के अंदर जायेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकेटेश्वर की मूर्ति गर्भ गृह के मध्य में स्थित है, पर जब आप गर्भ गृह से बाहर आकर मूर्ति को देखेंगे तो प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है।

तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित है लेकिन फिर भी भगवान की मूर्ति से समुद्र की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान की यह मूर्ति समुद्र से प्रकट हुई थी इसलिए इससे समुद्र की आवाज सुनाई देती है। तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर के द्वार पर एक छड़ी रखी हुई है। इस छड़ी को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु धरती पर माता लक्ष्मी को ढूंढ़ने आये थे तो यह छड़ी उन्हें उनका पता बता रही थी। ऐसी मान्यता है कि यह वहीं छड़ी है जिससे बचपन में भगवान वेंकटेश्वर जी को चोट लगी थी। चोट का निशान आज भी उनकी मूर्ति के चेहरे पर है। इसलिए हर शुक्रवार उनके चेहरे पर चन्दन का लेप लगाया जाता है। श्री तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में श्रृंगार, प्रसाद के चढ़ाये जाने वाली सामग्री तिरुपति बालाजी के गांव से आती है। यह गांव मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है। श्री वेंकेटेश्वर बालाजी मंदिर में एक ऐसा दीया रखा हुआ है जो हमेशा जलता रहता है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था यह बात अब तक रहस्य बनी हुई है।

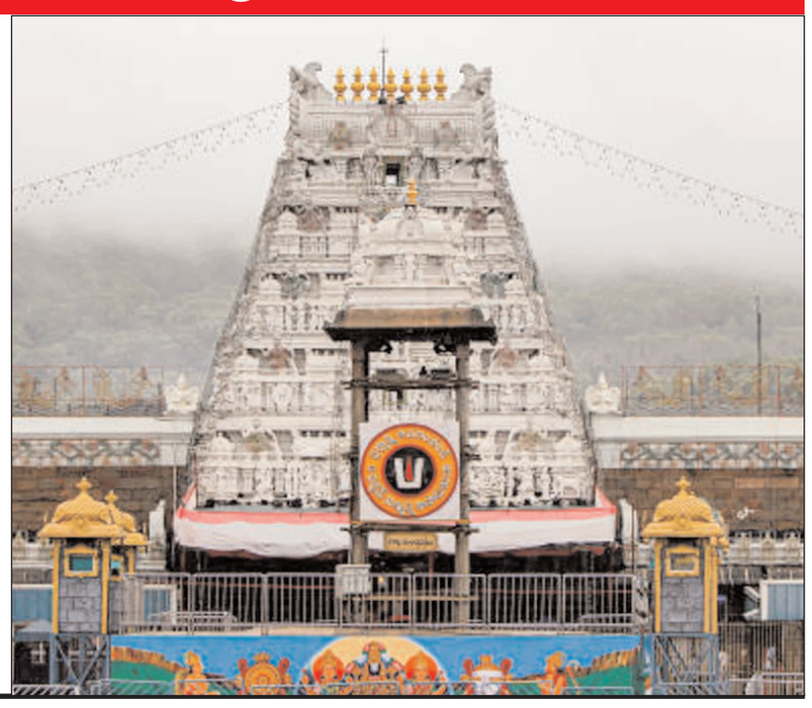

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

लालकृष्ण आडवाणी की सेहत में सुधार, एम्स से मिली छुट्टी

नईदिल्ली। बुधवार की रात नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराए गए वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने कहा कि भाजपा नेता स्थिर हैं। उनका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। 96 वर्षीय भाजपा नेता को इस साल की शुरुआत में चार अन्य लोगों के साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में आडवाणी भारत के उपप्रधानमंत्री रहे। आडवाणी और जनसंघ के कई अन्य सदस्यों ने 1980 में जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गठन किया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वालपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे। आडवाणी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1989 में नई दिल्ली सीट से लड़ा। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण की मांग के लिए रथ यात्रा शुरू की थी।

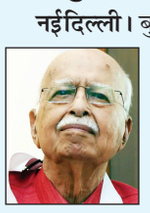

आप सासंदों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से पहले संसद परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। आप सांसदों ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की, इसे तीसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के गठन के बाद पहला राष्ट्रपति अभिभाषण माना जा रहा है। आप नेता संदीप पाठक ने न्याय की आड़ में तानाशाही कार्यों के खिलाफ विरोध करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो आवाज उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्यसभा में अपनी असहमति व्यक्त करेगी।

बहाल हुई आप सांसद संजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता

नईदिल्ली। पिछले साल मानसून सत्र के दौरान निलंबित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता गुरुवार को बहाल कर दी गई। अध्यक्ष के निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने के लिए उन्हें शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। आप नेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर खबर साझा करते हुए कहा कि उन्हें लगभग एक साल बाद राज्यसभा का अनुभव मिला है। उन्होंने उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ और विशेषाधिकार समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि लगभग एक साल के बाद संसद में जाने की अनुमति प्राप्त हुई। निलंबन खत्म हुआ। माननीय सभापति उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ जी, प्रिविलेज कमेटी के सभापति व सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत धन्यवाद व आभार। आप के वरिष्ठ नेता सिंह को जुलाई 2023 में अनियंत्रित व्यवहार के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।

अब प्रार्थना रहेगी तानाशाह का विनाश हो : सुनीता केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सीबीआई ने उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया। इसी घोटाले से जुड़े जांच एजेंसी ईडी के एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सदबुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि तानाशाही के खिलाफ संघर्ष की यह तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल झुकेगा नही जितना मर्जी अत्याचार कर लो। ईडी कोर्ट से जमानत के बाद सीबीआई की गिरफ़्तारी बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसी का खुला दुरुपयोग है।

तेलंगाना में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर तैयारी जारी

नई दिल्ली। तेलंगाना ने तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि इन नए कानूनों की अनुवाद प्रक्रिया भी चल रही है और इसके भी 1 जुलाई से पहले पूरी होने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना का मसौदा तैयार है और अगले कुछ दिनों में नए कानूनों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए कानूनों को सरकार की योजना के अनुसार लागू किया जाए, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं और तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी में आईपीएस अधिकारियों के लिए नए आपराधिक कानूनों पर एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई और उन्हें नए कानूनों की भावना के बारे में भी बताया गया।

संविधान पर सबसे बड़ा हमला था आपातकाल : राष्ट्रपति

■ द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बृहस्पतिवार को संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वागत किया। इस अवसर पर एक अधिकारी हाथ में 'राजदंड' (सेंगोल) लिए हुए था। राष्ट्रपति 18वीं लोकसभा के गठन और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार बनने के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि 1975 में लगाया गया आपातकाल भारत के संविधान पर सबसे बड़ा हमला और धब्बा था। इस साल आम चुनाव में नई लोकसभा चुने जाने के बाद संसद में यह उनका पहला संबोधन है। राष्ट्रपति ने सत्ता पक्ष की जय-जयकार और विपक्ष के विरोध के बीच कहा, 1975 में आपातकाल भारत के संविधान पर सबसे बड़ा हमला और उस पर एक धब्बा था।

यह हमला आपातकाल पर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की पृष्ठभूमि में आया है। जबकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों ने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की भयावहता पर जोर दिया है, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में अघोषित आपातकाल लागू है। राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा कि आने वाले महीनों में भारत लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। भारत के संविधान ने पिछले दशकों में हर चुनौती और बाधा का सामना किया है। संविधान लागू होने के बाद भी इस पर कई बार हमले हुए हैं।

उन्होंने कहा कि सबसे काला अध्याय 25 जून 1975 को आपातकाल के दौरान संविधान पर सीधा हमला था, जब पूरा देश निराशा की चीखों से गूंज उठा था। हालाँकि, भारत ने ऐसे असंवैधानिक दबावों पर विजय प्राप्त की क्योंकि भारत के मूल मूल्य हमेशा लोकतंत्र की परंपराओं में निहित रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा, मेरी सरकार ने सीएए कानून के तहत

शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के सुधार, परिवर्तन और प्रदर्शन के मंत्र ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। उन्होंने आगामी बजट को ऐतिहासिक और भविष्योन्मुखी दस्तावेज बताया, जो सुधारों को गति देगा और दूरगामी नीतियों को पेश करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान कहा आगामी सत्र में सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। यह बजट दूरगामी नीतियों और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का एक प्रभावशाली दस्तावेज होगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी सरकार में भरोसा जताया, उन्होंने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मिले जनादेश का हवाला देते हुए कहा कि यह उनके दशक भर के ट्रैक रिकॉर्ड को पुष्ट करता है। उन्होंने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए सुधारों को तेज करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रपति का भाषण आगामी संसदीय सत्रों में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर चर्चा के लिए मंच तैयार करता है, जिसमें देश के विकास के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, करोड़ों देशवासियों की ओर से मैं भारत के चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था...जम्मू-कश्मीर में मतदान के दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले 4 दशकों से कश्मीर में बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान हुआ है। भारत के दुश्मनों ने इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की राय के रूप में प्रचारित किया। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने ऐसी सभी ताकतों को करारा जवाब दिया है।

सशक्त भारत के लिए सैन्यबलों में आधुनिकता एवं आत्मनिर्भरता की जरूरत पर बल देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात 18 गुना अधिक हुआ है तथा फिलीपीन के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा, रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की पहचान मज़बूत कर रहा है।

नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध अलग-अलग बातें हैं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध, दो अलग-अलग बातें हैं और जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहां स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार पर ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर बनता है। राष्ट्रपति ने अपने लगभग 55 मिनट के अभिभाषण में कहा, ''मुझे भरोसा है कि संसद के पल-पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगी। मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कुछ और चिंताएं भी साझा करना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि आप सभी इन विषयों पर चिंतन-मनन करके, इन विषयों पर ठोस और सकारात्मक परिणाम देश को दें।'' उन्होंने कहा कि आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें, लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार डालने की साजिश रच रही हैं। मुर्मू ने कहा कि ये ताकतें देश के भीतर भी हैं और देश के बाहर से भी संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा अफवाह फैलाने का, जनता को भ्रम में डालने का, गलत सूचनाओं का सहारा लिया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा, ''इस स्थिति को ऐसे ही बेरोक-टोक नहीं चलने दिया जा सकता। आज के समय में प्रौद्योगिकी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक वैश्विक रूपरेखा की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इस प्रवृत्ति को रोकें, इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजें।'' उन्होंने कहा कि राष्ट्र की उपलब्धियों का निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में नव निर्वाचित सदस्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं, वहीं पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं।

उन्होंने कहा, ''आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद क्या निर्णय लेती हैं, क्या नीतियां बनाती हैं, इस पर पूरे विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, यह दायित्व सरकार के साथ-साथ संसद के हर सदस्य का भी है।'' मुर्मू ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में जो सुधार हुए हैं, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, उससे हम 'विकसित भारत' बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा, ''हम सभी को हमेशा यह ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा न हो, यह हम सभी का दायित्व है।''

उन्होंने कहा, ''हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें समानो मंत्र: समिति: समानी की प्रेरणा दी है। अर्थात, हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें। यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी।''

मुर्मू ने कहा, ''हम जब 2047 में आजादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे, तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्पों में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां हैं, यह इस बात का प्रमाण हैं कि आने वाला दौर भारत का दौर है। यह सदी भारत की सदी है, और इसका प्रभाव आने वाले एक हजार वर्षों तक रहेगा।'' उन्होंने अभिभाषण के अंत में कहा, ''आइए, हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं।''

पश्चिम बंगाल में विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर बढ़ी तकरार

विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे टीएमसी विधायक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। अब गुरुवार को टीएमसी विधायकों ने इस मुद्दे पर विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नवनिर्वाचित विधायक सयांतिका बंदोपाध्याय और रायत हुसैन सरकार ने विधानसभा परिसर में मौजूद डॉ. बी आर आंबेडकर की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन शुरू किया। विधायकों की मांग है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस उन्हें जल्द विधानसभा में शपथ दिलाने का इंतजाम करें ताकि वह अपने जनप्रतिनिधि के कर्तव्य को पूरा कर सकें।

गौरतलब है कि दोनों विधायक हाल ही में हुए उपचुनाव में जीते हैं। दोनों को बुधवार को राजभवन में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि, टीएमसी ने दावा किया कि परंपरा यह है कि उपचुनाव जीतने वाले विधायकों के मामले में राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, लेकिन राज्यपाल ने दोनों के अनुरोध के अनुसार विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित करने से इनकार कर दिया और 26 जून की शाम को नई दिल्ली चले गए। बंदोपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, %हमने बुधवार को शाम 4 बजे

तक राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का इंतजार किया, लेकिन वे नहीं आए। आज हम अंबेडकर की प्रतिमा के सामने इस मांग के साथ बैठे हैं कि लोगों के लिए काम करने के हमारे संवैधानिक अधिकारों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाए।%

विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने बुधवार को राज्यपाल बोस पर शपथ ग्रहण समारोह को अहं की लड़ाई बनाने और जानबूझकर इस मुद्दे को जटिल बनाने का आरोप लगाया। वहीं राज्यपाल बोस का कहना है कि %देश का संविधान उन्हें यह तय करने का अधिकार देता है कि विधायकों को शपथ दिलाने का काम किसे सौंपा जाए। मुझे विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्पीकर द्वारा राज्यपाल के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक पत्र को भेजने के बाद यह विकल्प संभव नहीं हो पाया।

खेल
प्रमुख समाचार

पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका

त्रिनिदाद। टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका ने अपने नाम की मुहर लगा दी है। साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। बता दें कि, ये पहली बार है जब अफ्रीकी टीम टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, इसके साथ ही टीम ने इतिहास भी रच दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम महज 56 गेंदों पर धराशाही हो गई, जिसके जवाब में अफ्रीकी टीम ने आसानी से इस टारगेट को चेज कर लिया। साउथ अफ्रीका के लिए रीजा हेंड्रिक्स ने 29 रन बनाए। वहीं कप्तान एडम मार्क्रम ने 23 रन बनाए। ये दोनों खिलाड़ी अंत तक आउट नहीं हुए और महज 8.5 ओवर्स में ही टारगेट को चेज कर लिया। टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। जब क्विंटन डिकॉक सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए उन्हें फजलहक फारूकी ने अपना शिकार बनाया।

इसके साथ ही अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बाद में गलत साबित हुआ। टीम के बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और कोई भी खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन नहीं कर सका। अजमतुल्लाह उमरजई ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए थे, उन्होंने 10 रन बनाए। जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज, नूर अहमद और मोहम्मद नबी अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इसी कारण से अफगानिस्तान टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और महज 56 रनों पर ही समिट गई। टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया ये सबसे कम स्कोर है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का प्रदर्शन काबिले तारीफ था। मार्को जेसन ने 3 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं तबरेज शम्सी ने भी तीन विकेट अपने नाम किए। कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्खिया ने 2-2 विकेट चटकाए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स पहली बार 79 हजार तो निफ्टी 24 हजार के पार

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को रिकॉर्ड-तोड़ तेजी दर्ज की गई जिससे बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए। घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर मजबूत आंकड़े, राजनितिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों की तरफ देसी शेयरों में खरीदारी से बाजार रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी से बाजार को हरे निशान में बंद होने में मदद मिली। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज तेजी के साथ 78,758.67 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 79,396.03 अंक उच्च स्तर तक चला गया था। अंत में सेंसेक्स 0.72 प्रतिशत या 568.93 अंक की छलांग के साथ 79,243.18 के एतिहासिक लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी-50 भी 0.74 फीसदी या 175.70 अंक की वृद्धि के साथ 24,044.50 अंक के ऑल टाइम हाई लेवल पर बंद हुआ।

अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीदी इंडिया सीमेंट्स की हिस्सेदारी

नईदिल्ली। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की करीब 23 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। अल्ट्राटेक ने गुरुवार 27 जून को घोषणा की है कि उसने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इसके तहत कंपनी 267 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 7 106 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी। इस अधिग्रहण से अल्ट्राटेक को इंडिया सीमेंट्स में 23 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी। 27 जून, 2024 को हुई बैठक में अल्ट्राटेक के निदेशक मंडल ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है। अल्ट्राटेक की इस घोषणा के बाद इंडिया सीमेंट्स के शेयरों में अपर सर्किट लग गया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्ट्राटेक की ओर से इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में किया गया निवेश पूरी तरह से फाइनेंशियल है। इसका संबंधित पक्ष से कोई लेनदेन नहीं है। इस निवेश का उद्देश्य सीमेंट इंडस्ट्री में अल्ट्राटेक की उपस्थिति को मजबूत करना है।

बेन कैपिटल समर्थित एमक्योर फार्मा तीन को लाएगी आईपीओ

नईदिल्ली। बेन कैपिटल समर्थित एमक्योर फार्मास्युटिकल्स तीन जुलाई को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए तैयार है। आईपीओ दस्तावेज के अनुसार, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम पांच जुलाई को बंद होगा। एंकर (बड़े) निवेशक दो जुलाई को बोली लगा पाएंगे। आईपीओ में 800 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर और 1.14 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। पुणे स्थित कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स कई प्रमुख चिकित्सीय क्षेत्रों में औषधि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास, विनिर्माण और वैश्विक स्तर पर विपणन का काम करती है।

स्पर्श सीसीटीवी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने करेगी निवेश

नईदिल्ली। स्पर्श सीसीटीवी की अगले पांच साल में 300 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। कंपनी सरकार के 'मेड इन इंडिया' (भारत निर्मित) निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिए जाने से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहती है। इस निवेश से इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणों की अग्रणी विनिर्माता कंपनी को अपने काशीपुर संयंत्र में परिचालन बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्पर्श सीसीटीवी के प्रबंध निदेशक संजीव सहगल ने बयान में कहा स्पर्श सीसीटीवी की मौजूदा क्षमता 25 लाख यूनिट प्रति वर्ष है। इस निवेश तथा काशीपुर सुविधा के बाद उत्पादन क्षमता 10 लाख यूनिट प्रति माह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण 'क्लस्टर 2.0' में उत्तराखंड के काशीपुर में एक प्रमुख इकाई स्थापित करेगी।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत पर जता रही भरोसा, विश्व में बढ़ रही है आर्थिक साख

प्रहलाद सबनानी

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पूअर ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करते हुए कहा है कि वह भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए आर्थिक विकास के विभिन्न पैमानों का व राजकोषीय घाटे से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर रही है। यदि दोनों क्षेत्रों में सुधार होता है, तो भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया जा सकता है। वर्तमान में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बीबीबी- है, जो निवेश के लिए सबसे कम रेटिंग की श्रेणी में आती है।

किसी भी देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने पर उस देश में विदेशी निवेश बढ़ने लगता है, क्योंकि निवेशकों को इन देशों में पूंजी निवेश तुलनात्मक रूप से

सुरक्षित लगता है। साथ ही, ऐसे देशों की कंपनियों के लिए अन्य देशों में पूंजी उगाहना न केवल आसान होता है, बल्कि ऋण पर भी कम ब्याज राशि देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान लिए गए आर्थिक निर्णयों का भरपूर लाभ देश को मिला है। भारत आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। देश में बड़े स्तर पर वित्तीय समावेशन हुआ है। जनधन योजना के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक बैंक बचत खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें करीब 2.50 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा है। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। देश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 2200 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है। कुछ राज्यों में किसानों की आय दोगुने से भी अधिक हो गई है। भारत में विदेशी निवेश भी भारी मात्रा में होने लगा है एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने लगी हैं। भारत में आर्थिक विकास की दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में आठ प्रतिशत से भी अधिक रही है।

भारत, अपने आर्थिक विकास की गति को और तेज करने के लिए आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लगातार प्रयास कर रहा है। आधारभूत ढांचे के विकास से उत्पादकता में सुधार हुआ है एवं उत्पादन लागत में कमी आई है। एस ऐंड पी का तो यह भी कहना है कि भारत जिस प्रकार की आर्थिक नीतियों को लागू करते हुए आगे बढ़ रहा है, उससे भारत की आर्थिक विकास दर को लंबे समय तक आठ प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा जा सकता है। भारत ने अपने राजकोषीय घाटे पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा 17 लाख 74 हजार करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 16 लाख 54 हजार करोड़ रुपये का रह गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देश भी अपने राजकोषीय घाटे को कम नहीं कर पा रहे हैं, परंतु भारत ने वर्ष 2023-24 के दौरान यह बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्र सरकार ने खर्च पर नियंत्रण किया है एवं अपनी आय के साधनों में अधिक वृद्धि की है। भारत के कुछ राज्यों (पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल आदि) में राजकोषीय घाटे को लेकर चिंता जताई जा रही है, परंतु केंद्र सरकार एवं कुछ अन्य राज्य (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आदि) अपने राजकोषीय घाटे को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर पा रहे हैं।

राजकोषीय घाटे को कम करने में भारत को इसलिए भी सफलता मिली है कि देश में 20 से अधिक करों को मिलाकर केवल एक कर प्रणाली, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) को लागू किया गया है। आज जीएसटी से भारत को औसत 1.75 लाख करोड़ रुपये की राशि प्रतिमाह अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त हो रही है। प्रत्यक्ष कर के संग्रहण में भी 20 प्रतिशत की वृद्धि दिखी है। कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का आकलन करने वाले विभिन्न संस्थान भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर बहुत उत्साहित हैं एवं उसे अपग्रेड करने पर गंभीरता से विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत संभव है कि स्टैंडर्ड एंड पूअर आगामी दो वर्षों में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दे।

मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम का हुआ आगाज

साय ने सुनी शिकायतें दिए त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार का पहला जनदर्शन कार्यक्रम आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाएगा। आम नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार को बने छह माह हुए हैं। इस दौरान लोगों से लगातार मुलाकातें हुई है, सभी से मिलने की मैं कोशिश करता रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता महसूस होती रही, जो केवल आम नागरिकों से मुलाकात के लिए हो। पूर्व में डॉ. रमन सिंह की सरकार के समय जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित होता था। अब उसी कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आज फिर से शुरू किया है। जनदर्शन कार्यक्रम प्रत्येक गुरूवार को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक गुरूवार को पूर्वान्ह 11 बजे से मध्यान्ह 1 बजे तक आम नागरिक से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं की सुनवाई करेंगे। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं, अपेक्षाओं, आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही इसे जनदर्शन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। आम जनता से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग द्वारा समय-सीमा में निराकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को देंगे।

महतारी वंदन की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को दी बधाई- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में मुलाकात के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री साय को प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाई दी और कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि से उन्हें अपने जरूरी कामों पूरा करने में मदद मिलने लगी है। इससे उनका सम्मान बढ़ा है और स्वाभिमान मजबूत हुआ है।

अब वे खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन दर्शन में आज रायपुर के श्याम नगर निवासी महाविद्यालय की छात्रा आयुषी द्विवेदी आई। आयुषी ने बताया कि मेरा सपना आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है। सपने में आर्थिक स्थिति बाधा है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं और इसके लिए उन्होंने मुझे खूब प्रेरित किया। दुर्भाग्य से कोरोना आया और उनका निधन हो गया। अब मेरा दो सपना है। एक तो मेरे पिता का सपना पूरा करना और दूसरा मेरे खुद का सपना पूरा करना। मुख्यमंत्री जी आप अगर मेरी सहायता करें तो मेरी रास्ते की बाधा दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुषी की तैयारी के लिए अधिकारियों को आवश्यक सुविधा एवं सहायता दिलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से अनेक दिव्यांगजनों से की भेंट। मुख्यमंत्री ने एक छोटे से दिव्यांग बच्चे को दुलारा, उसकी समस्या जानी। उसके परिजनों से बात की। स्वास्थ्य कियोस्क कर्मचारी संगठन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नर्सिंग प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री साय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार बीएड प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों और बस्तर संभाग से आए शिक्षकों ने भी भेंट की। देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर शहर के शांति नगर निवासियों की समितियों ने राखड से होने वाले दिक्कतों के बारे अवगत कराते हुए इस समस्या से मुक्ति दिलाने और स्वच्छता निरीक्षक के प्रतिनिधि मण्डल ने स्वच्छता निरीक्षकों की भर्ती की मांग की। धोबी महासंघ ने भी मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जनदर्शन कार्यक्रम में महाविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन, अनियमित कर्मचारी महासंघ ने भी ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री विष्णु

हमारी सरकार के लिए स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरिः मुख्यमंत्री

महिलाओं ने कहा कि आपकी सरकार ने हमारी जरूरतों को समझा है। हमें उम्मीद है कि आपकी सरकार आगे भी इसी तरह की संवेदनशीलता के साथ काम करती रहेगी। जनदर्शन में एक महिला अपने पति श्री रमेश शुक्ला की समस्या लेकर आई थी। पत्नी ने बताया कि उनके पति श्री शुक्ला कैंसर की बीमारी के एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने महिला को संबल देते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है। आपके पति को सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री की सहृदयता पर श्रीमती शुक्ला ने आभार जताते हुए कहा कि हम लोग जनदर्शन में बहुत उम्मीद लेकर आए थे। आप से मिलकर, मुझे अपने पति के जल्द और गुणवत्तापूर्ण इलाज का भरोसा मिला है आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। श्रीमती शुक्ला ने बताया कि उन्हें 2 दिन पूर्व जनदर्शन की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था कि सांसद और मंत्री रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों का इलाज कराया है। जनदर्शन में इसका मौका मिला तो मैं आई। मेरा यहां आना सफल हुआ है।

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने जनदर्शन पर किया कटाक्ष, कहा-

प्रदेश में सरकार कैसे चल रही है इसका रुझान सामने आ गया

रायपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जनदर्शन, बिजली बिल बढ़ोत्तरी, गौ तस्करी, धान उठाव में हो रही देरी, नामकरण जैसे मुद्दों पर मीडिया के सवालों पर जवाब दिया. उन्होंने साय सरकार के जनदर्शन पर कटाक्ष किया है. पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि पहले ही जनदर्शन से प्रदेश में सरकार कैसे चल रही है इसका रुझान सामने आ गया है. सत्ताधारी दल के विधायक पर पैसे लेने का आरोप लग रहा है, आईपीएस के परिजनों की शिकायत आ रही है. जनदर्शन तो छोड़िए प्रदेश भर कानून व्यवस्था किस हाल में यह पेंड्रा में घटित घटना से समझा जा सकता है. संरक्षित सिरपुर में जेसीबी से खुदाई की जा रही है. कीमती मूर्तियों की चोरी हो रही है. सरकार नाम की चीज ही गायब हो गई है.

गौ तस्करी का खेल मिलीभगत से हो रहा है- छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी मामले में सियासत गर्म है. बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष ने इस मामले में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि सत्ता और उससे जुड़े बजरंग दल, विहिप के बीच टकराव नजर आ रहा है. तस्करी का खेल मिलीभगत से हो रहा है. यह गम्भीर मामला है और इस पर सरकार फेल नजर आ रही है.

बिजली हॉफ जरूर हो गई- बिजली बिल की बढ़ोत्तरी पर मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली बिल माफ तो नहीं हुआ लेकिन बिजली हॉफ जरूर हो गई है. पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि बिजली कटौती सांय-सांय चल रही है. बिल आंय-बाय आ रहा है. प्रदेश में लोग अघोषित कटौती से परेशान हैं. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने का मामला सामने आया है. उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश भर से यह ऐसी जानकारी आ रही है कि लाखों क्विंटल धान का उठाव नहीं हुआ है. सोसायटी में शार्टेज का आरोप कर्मचारियों पर लग रहा है. कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है. सरकार की गलती की सजा कर्मचारियों क्यों? - छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा. लेकिन सत्र से पहले ही सियायत शुरू हो गई है. विपक्ष ने सत्र छोटा रखने पर सवाल उठाया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो भाजपा छोटे सत्र को लेकर हंगामा करती थी. अब 5 दिन की बैठक रखकर सत्र चलाना चाहती है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे तैयार हैं. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कल से समीक्षा बैठक की शुरुआत होने जा रही है. कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं की कमेटी बनी है.

राज्य के सभी न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों को सर्वसुविधा युक्त आवास उपलब्ध हों: सिन्हा

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जिला उत्तर बस्तर कांकेर के सिंगारभाट एवं पखांजुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए नव निर्मित आवास गृहों का वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने कहा कि जितना सुन्दर व साफ सुथरा आवास गृह कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, उसे निवास के दौरान स्वच्छ रखें। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि राज्य के न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने की पहल की गई है जिसके तारतम्य में यह लोकार्पण हुआ। जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि नवनिर्मित न्यायिक आवासीय मकानों में सभी आवश्यक सुविधाए हो, और उनका कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। मुख्य न्यायाधिपति के साथ विशिष्ट

अतिथि के रूप में छ.ग. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पोर्टफोलियो न्यायाधीश संजय एस अग्रवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार ध्रुव ने मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा एवं न्यायाधीश श्री संजय एस अग्रवाल का स्वागत करते हुए सिंगारभाट कांकेर एवं पखांजुर में नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त आवासीय कालोनी की सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि सिंगारभाट कांकेर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए 88 मकान बना है एवं पखांजुर में कुल 11 मकान बना है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि मुख्य न्यायाधिपति ने एवं कुशल नेतृत्व से छत्तीसगढ़ के सुदूर जिला एवं तहसील का निरीक्षण कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय कराया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी — प्रमुख समाचार

मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप, प्रभारी सिविल सर्जन निलंबित

रायपुर। कोरिया जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार डॉ. राजेन्द्र बंसारिया, अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर द्वारा मरीज का ऑपरेशन करने हेतु राशि की मांग की गई थी तथा मरीज के परिजनों द्वारा राशि नहीं दिए जाने के कारण मरीज का इलाज नहीं किया गया। डॉ. बंसारिया के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। अतः राज्य शासन ने डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉ. राजेन्द्र बंसारिया मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते के नियमानुसार पात्र होंगे।

रामभक्तों की सेवा से छत्तीसगढ़ हुआ धन्य-मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सेवा कर लौटे छत्तीसगढ़ के सभी रामसेवकों का अपने निवास परिसर में स्वागत एवं अभिनंदन किया। साय ने सभी रामभक्त 6 समितियों को शाल श्रीफल और श्री रामलला की धातु की मूर्ति भेंटकर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सेवा कर लौटे प्रभु श्री रामलला दर्शन अभियान समिति के अंतर्गत सभी 6 समितियों के साथ भोजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी समितियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजित होने के साथ ही रामभक्तों की 500 सालों की मनोकामना पूर्ण हुई है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रभु श्रीराम का ननिहाल हमारा छत्तीसगढ़ है और हम भांचा के रूप में श्री राम को पूजते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के इन 6 समितियों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि ये समितियां स्वमेव प्रेरित होकर अयोध्या पहुंची.

20 थानेदारों का तबादलाष्ट

रायपुर। जिले के 20 निरीक्षकों को इधर से उधर कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने देर रात सूची जारी कर रक्षित आरक्षित केंद्र सहित थाना व यातायात व्यवस्था में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए तबादला आदेश जारी किया है। अधिकारी का नाम - वर्तमान पदस्थापना -नवीन पदस्थापना, मल्लिका बैनर्जी तिवारी -रक्षित केंद्र- थाना प्रभारी पंडरी, सुनील दास - रक्षित केंद्र -थाना प्रभारी आमानाका, राजेंद्र दीवान - रक्षित केंद्र -थाना प्रभारी धरसींवा, विशाल कुजुर- रक्षित केंद्र -यातायात, दीपेश जायसवाल -थाना प्रभारी आमानाका -थाना प्रभारी कबीर नगर, दीपक पासवान- थाना प्रभारी गंज -थाना प्रभारी खरोरा, लखन लाल पटले -थाना प्रभारी सरस्वती नगर- थाना प्रभारी गंज, जितेंद्र ऐसैय्या -थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा -थाना प्रभारी गोबरा नवापारा, राजेश सिंह -यातायात -थाना प्रभारी आरंग, शिवेंद्र राजपूत- थाना प्रभारी धरसींवा -थाना प्रभारी डीडी नगर, सुरेंद्र श्रीवास्तव -थाना प्रभारी खरोरा- थाना प्रभारी सरस्वती नगर, अविनाश सिंह -थाना प्रभारी डीडी नगर- थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा, सत्येंद्र सिंह श्याम -थाना प्रभारी आरंग -प्रभारी जिविशा, श्रुति सिंह -थाना प्रभारी खम्हारडीह -प्रभारी पुलिस नियंत्रण कक्ष, डीसीबी, डीसीआरबी, मनोज नायक- थाना प्रभारी मौदहापारा - प्रभारी शिकायत शाखा, सीसीटीएनएस, शील आदित्य कुमार सिंह -थाना प्रभारी पंडरी -यातायात, रविंद्र कुमार यादव -थाना प्रभारी कबीर -नगर यातायात, सिद्धेश्वर प्रताप सिंह -यातायात -थाना प्रभारी अभनपुर, यामन देवांगन -थाना सिविल लाइन -थाना प्रभारी मौदहापारा *नरेंद्र मिश्रा -थाना प्रभारी जिविशा, कंट्रोल रुम -थाना प्रभारी खम्हारडीह .

निविदा के बाद अब तुरंत काम होगा शुरू, पीडब्लूडी ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूर्ण करने राज्य शासन द्वारा निविदा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सड़क और सेतु निर्माण के लिए निविदा के पहले संबंधित कार्यपालन अभियंता को प्रमाणित करना होगा कि कार्य के लिए 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण के लिए पूरी जमीन व्यवधानरहित होने पर ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव द्वारा विभागीय कार्यों में तेजी और कसावट लाने के निर्देश के बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता सहित सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। विभाग ने नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इनका समुचित पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा मंत्रालय से प्रमुख अभियंता से लेकर सभी कार्यपालन अभियंताओं को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि सड़क निर्माण के लिए सड़क की प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया गया है.

सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज

रायपुर। एसीबी की विशेष अदालत ने कोल घोटाला मामले में पेश सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। एसीबी की तरफ से डॉ. सौरभ कुमार पांडे और बचाव पक्ष से बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील हर्षवर्धन परघनिया और फैज़ल रिजवी ने पैरवी की। सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 से लगातार केंद्रीय जेल में निरुद्ध हैं। रायपुर विशेष अदालत (एसीबी/इओडब्लू) की जज निधि शर्मा तिवारी ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दिया। अदालत ने ज़मानत याचिका आवेदन को खारिज करते हुए आदेश में लिखा है कि केस डायरी में उल्लेखित सामग्री से आरोपित अपराध में अभियुक्ता / आवेदिका की प्रथम दृष्टया संलिप्तता होना दर्शित है। ज़मानत दिए जाने पर अन्वेषण को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

नवभारत साक्षरता कार्यक्रमः असाक्षरों को साक्षर बनाने चलेगा अभियान

15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को शत-प्रतिशत साक्षर किए जाने का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में असाक्षरों को साक्षर करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ''उल्लास'' का संचालन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 15 वर्ष से अधिक उम्र के शत-प्रतिशत असाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा राज्य में उल्लास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय व समग्र शिक्षा के समन्वय से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। कार्यक्रम में अकादमिक सहयोग राज्य साक्षरता केन्द्र द्वारा किया जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के सीईओ को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक सभी युवा, प्रौढ़, पुरुष एवं महिलाओं को शत-प्रतिशत बुनियादी साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साक्षरता केवल पढ़ना लिखना और अंक ज्ञान में आत्मनिर्भर होना ही नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर कार्यात्मकता, सशक्तिकरण तथा आगे सीखते रहना है।

साक्षरता एक व्यक्ति के लिए बेहतर आजीविका व अवसरों तक पहुंचने के लिए जरूरी है। समुदाय के लिए समाज की एकता व सबके स्वास्थ्य व शिक्षा हेतु जरूरी है। साक्षरता देश के लिए जनतंत्र की मजबूती व आर्थिक तरक्की एवं विकास हेतु जरूरी है। केन्द्र सरकार की सहायता से संचालित होने वाले इस उल्लास कार्यक्रम में आकांक्षी जिले एवं वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले, राष्ट्रीय और राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम दर वाले जिले में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा।

इसके अलावा ऐसे स्थान जहां अनुसूचितजाति, जनजाति और अल्पसंख्य बहुल आबादी वाले जिले, शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में पहले चरण में 15 से 35 आयु वर्ग के असाक्षरों और उसके बाद 35 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को साक्षर बनाने का काम किया जाएगा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हांकित स्कूलों में उल्लास साक्षरता केन्द्र (सामाजिक चेतना केन्द्र) स्थापित किया जाएगा। जहां असाक्षरों को 200 घण्टे का अध्यापन कराकर बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान प्रदान कराकर नवसाक्षर बनाया जाएगा।

नवसाक्षरों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास, सतत् शिक्षा-शिक्षार्थियों को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल मनोरंजन एवं स्थानीय रूचि के अनुसार अन्य विषय में उन्नत सामग्री प्रदान करना है।

महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के आरोपियों की बढ़ी न्यायिक रिमांड की अवधि

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में आरोपियों को राहत नहीं मिली है. एसीबी/ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने जेल में बंद आरोपियों चंद्रभूषण वर्मा, राहुल वकटे, रितेश यादव, भीम यादव, अमित अग्रवाल, सुनील दम्मानी और सतीश चंद्राकर और अर्जुन यादव की न्यायिक रिमांड 10 जुलाई तक बढ़ा दी है. बता दें कि महादेव एप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया है. इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे. एप के जरिये क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी. अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए एप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले. इस एप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था. महादेव बेटिंग एप कई ब्रांच से चलता था. छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक एप के मेन प्रमोटर हैं. ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते थे. हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे.

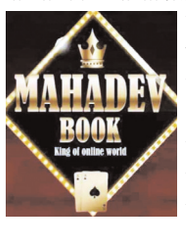

यूजर को शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता. इसे ऐसे बनाया गया था कि सिर्फ 30 फीसदी यूजर जीतते, बाकी हार जाते. इस एप के जरिए हुई कमाई को हवाला के जरिए होटल कारोबार और फिल्मों में लगाया गया.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.